A Daily News Magazine

इंदौर

बुधवार, 07 जनवरी, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 98, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

अब असम में 37 लाख महिलाओं को 8 हजार रुपये का 'तोहफा' !

दिलीप कुमार शर्मा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले दिनों बिहार में वोटरों को नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) के पक्ष में प्रभावित करने का दावा करते हुए कहा था, 'जब हमने बेहाली, नलबाड़ी, ढेकियाजुली में सबल महिला,सबल समाज स्कीम शुरू की, तो बिहार सरकार को भी अलग-अलग मीडिया के ज़रिए इसके बारे में पता चला। वे जानना चाहते थे कि हमने ये स्कीमें क्यों और कैसे शुरू की हैं। हमने समझाया कि हमारा मकसद हर महिला को 'लखपति बाइदेओ' (लखपति बहन) बनाना है।'

अब असम विधानसभा चुनाव से महज चार महीने पहले सीएम सरमा ने महिला लाभार्थियों के लिए नकदी स्कीम की घोषणा कर सत्ता में वापसी का दांव खेल दिया है। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री सरमा ने राज्य की 37 लाख महिलाओं को अपनी प्रमुख अरुणोदय योजना के तहत 8 हज़ार रुपये का 'बिहू उपहार' के तौर पर देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, 'चुनाव के समय अरुणोदय योजना का वितरण हमेशा एक विवादित विषय बन जाता है। विपक्ष भी कई बार आपत्ति जताता है। लिहाज़ा 20 फरवरी को असम की प्रत्येक अरुणोदय योजना की लाभार्थी को बिहू के उपहार के तौर पर 8 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। हम जनवरी में इस योजना का पैसा नहीं देंगे लेकिन 20 फरवरी को एक साथ बोहाग बिहू उत्सव के उपहार के तौर पर 8 हज़ार रुपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे।' एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा 'जनवरी से अप्रैल तक अरुणोदय योजना का पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए एक साथ हम 8 हज़ार रुपये दे रहे हैं। फिर मई से हर महीने मिलते रहेंगे। जनवरी से अप्रैल तक 1250 रुपये के हिसाब से 5 हज़ार होते हैं और हमने इसमें 3 हज़ार रुपये अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं।'

'अरुणोदय' एक वित्तीय सहायता योजना है जिसमें हर महीने महिला लाभार्थी के बैंक में सीधे 1250 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। 2020 में शुरू हुई इस योजना में अभी लगभग 37 लाख लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री ने एक और नई लाभार्थी योजना की घोषणा करते हुए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पुरुष छात्रों को हर महीने वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। इस 'बाबू योजना' के तहत सरकार 1 फरवरी से योग्य पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने 2000 रुपये और योग्य अंडर ग्रेजुएट छात्रों को 1000 रुपये की वित्तीय मदद देगी। इस का फ़ायदा उन छात्रों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना घरेलू आय 4 लाख रुपये तक होगी।

असम की राजनीति समझने वाले लोग विधानसभा चुनाव से पूर्व वित्तीय मदद से जुड़ी इन घोषणाओं को सभी मुद्दों का जवाब नहीं मानते। डिब्रूगढ़ विवि के राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर कौस्तुभ डेका ने कहा, 'निश्चित तौर पर इस तरह की घोषणाओं का चुनावी फ़ायदा तो मिलेगा। लेकिन असम में काफ़ी सारे अलग-अलग फैक्टर हैं। पहचान का मुद्दा है, बेरोज़गारी है। लिहाज़ा इस तरह की स्कीमों से सारे मुद्दों का जवाब नहीं दिया जा सकता। लोग जनजाति दर्जा देने की मांग, प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे। जिनके घर तोड़े गए उनकी भी मदद हो।'

इससे पहले राज्य सरकार ने बाल विवाह से निपटने के तरीके के तौर पर 12वीं से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की छात्राओं को हर महीने वित्तीय मदद देने के लिए 2024 में 'निजुत मोइना' योजना शुरू की थी। इस के तहत कक्षा 11वीं की छात्राओं के लिए 10 महीने तक हर महीने 1000 रुपये, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए 10 महीने तक हर महीने 1,250 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट तथा बीएड कोर्स की छात्राओं के लिए 10 महीने तक हर महीने 2500 रुपये निर्धारित हैं। असम विधानसभा चुनाव का ऐलान फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत में होने की उम्मीद है। उधर विपक्षी कांग्रेस ज़मीनी स्तर पर काफ़ी सक्रियता के साथ मतदाताओं से मिलकर एक ऐसा चुनावी घोषणा-पत्र तैयार करना चाहती है जिसमें बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सारी बातें हो। असम प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर गोस्वामी मानती है कि इस तरह की योजनाओं से थोड़ी बहुत चुनौती तो ज़रूर खड़ी होगी। लेकिन यह चुनौती तब तक है जब तक असम की महिलाएं राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सतर्क नहीं हो जातीं। महिलाओं को सोचना होगा कि एक तरफ स्कूल बंद किए जा रहे हैं और 1250 रुपये देकर उनका वोट ले लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री को यह आभास हो गया है कि बेरोज़गार, युवा, किसान, छोटे व्यापारी उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए महिला मतदाताओं को अपना लक्ष्य बनाया है। महिलाओं को समझना होगा कि यह 8 हज़ार रुपये का उपहार दरअसल चुनाव जीतने के लिए है।

असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। चर्चा है कि प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत को लेकर लोगों में जो नाराज़गी है, उसके कारण बीजेपी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही यहां चुनाव लड़े। वरिष्ठ पत्रकार नव कुमार ठाकुरिया कहते हैं, 'जुबिन गर्ग की घटना से पहले तक असम में बीजेपी के लिए किसी तरह की कोई चुनौती नहीं थी। सरकार और पार्टी के स्तर पर इस मामले को जिस तरह से संभालने का प्रयास हो रहा है, ऐसे में यह संभव है कि बीजेपी बिना किसी नेता को प्रोजेक्ट किए इस बार का चुनाव लड़े। लिहाज़ा सीएम हिमंत इस तरह की जन लुभावन स्कीमों की घोषणा कर रहे हैं ताकि मतदाताओं में उनकी पकड़ मज़बूत बनी रहे। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में एक अच्छा संदेश जाए। बीजेपी चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री भी बदल सकती है।'

कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता ने कहा, 'महिलाओं को आर्थिक तौर पर मज़बूत करना और उन्हें स्वनिर्भर बनाना हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। चुनाव के कारण अरुणोदय योजना का पैसा माताओं और बहनों को नहीं मिल पाता, लिहाज़ा हमारे सीएम ने उन्हें एक साथ एडवांस में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार में युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी मिली है। नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी गई है। सीएम ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कोर्ट की कार्यवाही में तेज़ी लाने के लिए खास तौर पर एक स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर नियुक्त करने जा रही है।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

जिन लड़कियों के हिस्से मां का
प्रेम नहीं आया
उनके हिस्से इंतजार भी नहीं आया
इस बात से वह अंदर ही अंदर
घिसती रहीं
उनकी आंखे भी हरदम रिसती रहीं
उन्हें गले से तो लगाया गया
पर गले से लगाने का सा अहसास
नहीं आया
उन्हें मां बहुत याद आई रसोई में
हाथ जलने पर
और याद आई अपनी बिटिया के
मचलने पर भी
सास ने जब ननद को दुलारा तब
मां याद आई
मायके में आंगन को जब बुहारा
तब मां याद आई
भतीजे के मुंडन पर,अपनी बातों
के खंडन पर
तीज त्योहारी में,मायके की फूली
फुलबारी में
बिटिया को मां जोरों से याद आई
सावन की हरियाली में,आंगन की
खुशहाली में
कमरे के अकेलेपन में,ससुराल के
तीखेपन में
पति के रूखेपन में,अपने जीवन
के सूखेपन में
बचपन में,जवानी में
अलहड़पन और हर नादानी में
विदा होती हर कहानी में
बस मां ही तो याद आई है!!

– प्रशांत कुमार मिश्रा

उप्र में SIR लिस्ट जारी, लाखों फर्जी नामों पर लटकी तलवार

- पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ नाम कटे
- अब 12.55 करोड़ वोटर्स,30 दिन का समय

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में की पहली ड्राफ्ट सूची जारी हो गई है। अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी विस्तार से जानकारी दी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जो पहले 15.44 करोड़ थे। यानी पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ (18 फीसदी) नाम कट गए। आज यानी 6 जनवरी से दावे-आपत्तियां की जा सकती हैं। जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 6 फरवरी तक फॉर्म 6 या 7 भरकर जमा कर सकते हैं। ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। दावा-आपत्ति के लिए फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। दावे और आपत्तियां मुफ्त हैं। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर- 1950 जारी किया है, जहां सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाएगा।

- **1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे लोग फार्म भर सकते हैं**–राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया– 1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे लोग फार्म भर सकते हैं। 1 अक्टूबर से जो एलिजेबल हो रहे हैं, वे फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया– एपिक नंबर से भी सर्च किया जा सकता है। ईसीआई नेट एप पर भी जानकारी देखी जा सकती है। नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दें। फॉर्म–8 करेक्शन के लिए भरा जाएगा। फार्म 7 डिलीट कराने के लिए भरा जाएगा। 6–ए विदेश में रहने वालों के लिए हैं।

बांग्लादेश में 18 दिन में छठे हिंदू की हत्या

हिंदू दुकानदार पर धारदार हथियार से किया हमला

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। यह बीते 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की हत्या है। शरत चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। इसी दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए अहम फैसले

बुरहानपुर जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,598 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना लागत 922 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना से खकनार तहसील के 42 ग्रामों की 17 हजार 700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिससे 11 हजार 800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे।

- **पीएम जनमन योजना की निरंतरता के लिए 795 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति**
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 17,196 करोड़ की स्वीकृति**

मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 1,676 करोड़ 6 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना से खकनार तहसील के 90 ग्रामों की 34 हजार 100 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी और 22 हजार 600 कृषक परिवारों को लाभ मिलना अनुमानित है।

पीएम जनमन योजना की निरंतरता की स्वीकृति- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में अनुमानित व्यय 795 करोड़ 45 लाख रुपये होगा। इसके तहत 1,039 किमी सड़क का निर्माण एवं 112 पुल निर्माण किया जायेगा। यह योजना 22 जिलों में निवासकरने वाली 3 विशेष जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिए लागू है।

मंत्रि- परिषद द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनांतर्गत अनुमानित व्यय 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपये है। योजना में 88 हजार 517 किमी मार्गों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा। मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्री-परिषद सदस्यों को मिले टैबलेट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में एक नए नवाचार करते हुए आज मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों को टैबलेट वितरण किया। उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्रालय में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कैबिनेट के सदस्यों और मंत्रि-परिषद के भारसाधक सचिवों को टैबलेट प्रदाय करने की शुरूआत हुई। कैबिनेट के सदस्यों ने टैबलेट प्राप्त किए और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत ई-कैबिनेट की पहल हुई है। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में संबंधितों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह एप्लीकेशन आधुनिक तकनीक, पेपरलैस, सुरक्षित और ऐसी गोपनीय प्रणाली है, जिसे मंत्रि-परिषद सदस्य कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार अवलोकन कर सकते हैं। मुख्य रूप से मंत्रि-परिषद की कार्य सूची देखने, ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन-प्रतिवेदन देखने में सुविधा होगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की निरंतरता की स्वीकृति

मंत्रि- परिषद द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनांतर्गत अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ 21 लाख रुपये होगा। इसके तहत 20 हजार किमी सड़क और 1200 पुल का निर्माण किया जायेगा।

देश में अब बदल जाएगा जीडीपी का नाम !

- अर्थव्यवस्था मापने के तरीके में बदलाव की तैयारी हो गई शुरू

जीडीपी की जगह एनडीपी को पैमाना बनाना चाहती है सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने की सोच रहा है। अब तक हम सकल घरेलू उत्पाद (ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी) को ही अर्थव्यवस्था का मुख्य पैमाना मानते आए हैं। लेकिन अब सरकार शुद्ध घरेलू उत्पाद (नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी) को ज्यादा अहमियत देने पर विचार कर रही है। यह बदलाव संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय खातों की प्रणाली 2025 के तहत किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एसएनए 2025 के अनुसार एनडीपी को जीडीपी जैसे सकल मापों से वैचारिक रूप से बेहतर बताया गया है। इसका मतलब है कि एनडीपी उत्पादन की असली लागत को ज्यादा अच्छे से बताता है। यह जीडीपी की तुलना में संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी (डेप्रिसिएशन) और प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने (डिप्लीशन) को भी ध्यान में रखता है। अभी भारत समेत दुनिया भर में जीडीपी ही अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत फिलहाल जीडीपी के साथ-साथ एनडीपी के सालाना अनुमान भी जारी करता है, लेकिन तिमाही एनडीपी के आंकड़े नहीं देता। हाल ही में 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2 फीसदी रही, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। 2024-25 के लिए जीडीपी और एनडीपी दोनों में पिछले साल की तुलना में 6.5 फीसदी की वृद्धि हुई। एनडीपी की गणना जीडीपी में से फिक्स्ड एसेट्स (स्थायी संपत्तियों) के डेप्रिसिएशन और प्राकृतिक संसाधनों के डिप्लीशन को घटाकर की जाती है। डेप्रिसिएशन का मतलब है उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली पूंजी के मूल्य में आई कमी। वहीं, रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उनकी मात्रा में आई कमी और भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान को दर्शाता है।

दिल्ली के पलूशन से फिर बीमार हुई सोनिया गांधी

सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद कराया एडमिट

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उन्हें सीने में दर्द की समस्या थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति पूरी तरह सामान्य है और चेस्ट फिजिशियन की निगरानी में उन्हें रखा गया है। अस्पताल के एक सूत्र ने कहा कि वह रुटीन चेकअप के लिए ही आई हैं, लेकिन उन्हें खांसी की समस्या काफी ज्यादा है। विशेष तौर पर दिल्ली में बढ़े हुए पलूशन के चलते उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती रहती हैं। एक बार फिर से ऐसी ही समस्या उभरने की आशंका है। वह सोमवार की रात को अस्पताल पहुंची थीं और फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। बीते साल ही वह 79 वर्ष की हुई थीं। सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी जांच करने पर पाया गया कि उन्हें अस्थमा की समस्या थोड़ी बढ़ गई है। ऐसा सर्दी के मौसम और पलूशन के चलते हुआ है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 07 जनवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

जैसलमेर का 'सोने' जैसा रंग, सांगानेर में बदलेगी सूरत

रेलवे का 248 करोड़ वाला प्लान तैयार, होगा कायाकल्प

जैसलमेर (एजेंसी)। राजस्थान की स्वर्णनगरी जैसलमेर और जयपुर के सांगानेर की सूरत बदल जाएगी। राजस्थान में 248 करोड़ की लागत से दो बड़े रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। जैसलमेर रेलवे स्टेशन 140 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो चुका है, जबकि 108 करोड़ की लागत से जयपुर के सांगानेर रेलवे स्टेशन की सूरत बदलेगी जाएगी। आज सांगानेर स्टेशन का शिलान्यास कार्यक्रम था, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे रद्द कर दिया गया है। फिलहाल कार्यक्रम की नई तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि जैसलमेर और जयपुर के सांगानेर में बनने जा रहे दोनों स्टेशन में जहां राजस्थान की सांस्कृतिक की झलक दिखेगी। वहीं आधुनिक भारत भी दिखेगा। स्टेशन के डिजाइन में राजस्थान की लोक कला, पत्थर की नक्काशी और

राजस्थानी वास्तुकला को शामिल किया गया है। रेलवे स्टेशन विश्वस्तरीय सुविधाओं मिलेगी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना की जीवंत तस्वीर पेश करेंगे। यहां आधुनिक वेटिंग एरिया, डिजिटल सूचना प्रणाली, एस्केलेटर और लिफ्ट, दिव्यांगजन फ्रेंडली रैम्प, बेहतर प्लेटफॉर्म शेल्टर, स्वच्छ टॉयलेट्स, और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था यात्रियों को दी जाएगी। यानी दोनों स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 140 करोड़ की लागत से री-डेवलप हुए रेलवे स्टेशन का काम दिसंबर लगभग में पूरा चुका है। अब इस रेलवे स्टेशन

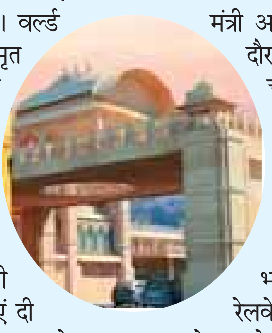

के औपचारिक उद्घाटन का इंतजार है। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसलमेर पहुंचे थे। इस दौरान कहा था कि रेलवे स्टेशन है, हम चाहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करे। ऐसा में माना जा रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतिम छोर पर बने इस रेलवे स्टेशन का इसी साल उद्घाटन हो सकता है। रेलवे अधिकारियों से अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सांगानेर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा दो साल पहले हो गई थी। लेकिन स्टेशन परिसर से गुजर रही बीसलपुर पेयजल लाइन की चलते इसका काम शुरू नहीं हो सका।

भगवंत मान तीसरे सीएम, जो अकाल तख्त पर पेश होंगे

- महाराजा से लेकर राष्ट्रपति तक ने यहां की सजा है भुगती

जालंधर (एजेंसी)। सिखों के सर्वोच्च श्री अकाल तख्त ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को तलब किया है। उन्हें 15 जनवरी को अकाल तख्त के सचिवालय में पेश होने को कहा गया है। सीएम मान ने भी कहा कि वह एक विनम्र सिख की तरह

नंगे पैर अकाल तख्त पर पेश होंगे। जहां वे अकाल तख्त जत्थेदार की तरफ से उठाए सवालों के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। अकाल तख्त में तलब होने वाले सीएम भगवंत मान तीसरे मुख्यमंत्री होंगे। इससे नहले दिवंगत सुरजीत सिंह बरनाला, प्रकाश सिंह बादल को भी अकाल तख्त में तलब किया जा चुका है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ये सजा भुगत चुके हैं।

कार्तिगई दीपम विवाद, हाईकोर्ट ने दीप जलाने की परमीशन दी

- स्टालिन सरकार ने जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश नहीं माना था

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को तिरुप्परनकुंड्रम मंदिर में पहाड़ी पर दरगाह के पास दीपस्तंभ (दीपथून) पर दीप जलाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन की बेंच ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के सिंगल बेंच का

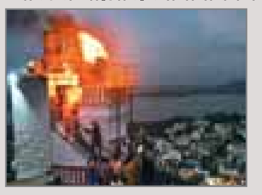

फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि यह लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को इस मामले को समुदायों के बीच संवाद और समन्वय के अवसर के रूप में देखना चाहिए था। यह मामला हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार की याचिका से जुड़ा है।

विदेश से लौटते ही 'ऐक्शन मोड' में तेजस्वी

- आधी रात को लालू यादव के साथ बंद कमरे में मंथन

पटना (एजेंसी)। लगभग एक महीने तक विदेश दौरे पर रहने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव भारत लौट आए हैं। रविवार को दिल्ली पहुंचने के बाद सोमवार की देर रात उन्होंने पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद

यादव से मुलाकात की। तेजस्वी की इस मुलाकात को महज एक पारिवारिक भेंट नहीं माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, लालू और तेजस्वी के बीच घंटों चली इस बैठक में बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और राजद के भविष्य के रोडमैप पर गंभीर चर्चा हुई। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी को फिर से संगठित करने और विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने की योजना पर विस्तार से बात की गई। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति के दौरान भाजपा और जदयू ने उन पर निशाना साधा था।

मगरमच्छों के शिकार बन रहे घड़ियाल

चंबल सेंचुरी में रेडियो ट्रांसमीटर से खुलासा, सबसे सुरक्षित गढ़ में ही शिकार, अफसर उपाय तलाश रहे

मुरैना (नप्र)। मध्य प्रदेश में घड़ियालों पर सीधा हमला हो रहा है। जिस नदी को देश में घड़ियालों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है, वहीं अब उनके बच्चों की जान खतरे में है। 435 किलोमीटर तक फैले चंबल घड़ियाल सेंचुरी की हालिया निगरानी में खुलासा हुआ है कि तीन साल तक के करीब 120 सेंटीमीटर लंबे घड़ियाल, लगातार मगरमच्छों के हमले का शिकार हो रहे हैं।

वन विभाग की 'गो एंड रिलीज' योजना के तहत घड़ियालों पर लगाए गए रेडियो ट्रांसमीटर से इसकी पुष्टि हुई है। ट्रांसमीटर सही सलामत मिले, लेकिन उनकी लोकेशन नदी में नहीं, बल्कि मगरमच्छों के पेट से ट्रेस हुई। जांच आगे बढ़ी तो मगरमच्छ के मल में घड़ियाल के अवशेष मिलने से इस पर मुहर लग गई।

चंबल घड़ियाल सेंचुरी में पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। मुरैना से भोपाल तक अफसरों की टीमें अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर घड़ियालों का सबसे सुरक्षित गढ़ कैसे उनकी शिकारगाह बनता जा रहा है।

1978-79 में बनी थी घड़ियाल सेंचुरी- देश में घड़ियालों के सुरक्षित संरक्षण के लिए जब नदियों का अध्ययन किया गया, तो चंबल नदी को सबसे स्वच्छ और अनुकूल पाया गया। साफ पानी और उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण में ही घड़ियाल बेहतर तरीके से जीवित रह पाते हैं। इसी आधार पर 1978-79 में मुरैना

जिले के देवरी गांव के पास देवरी घड़ियाल सेंचुरी की स्थापना की गई।

शुरुआत में चंबल नदी की बीच धारा से पांच किलोमीटर क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव था, लेकिन इससे कई गांव प्रभावित हो रहे थे। इसके आधार पर नदी की मध्य धारा से एक किलोमीटर क्षेत्र को चंबल घड़ियाल सेंचुरी के रूप में चिह्नित किया गया।

यह घड़ियाल सेंचुरी कुल 435 किलोमीटर तक फैली है। यहां घड़ियालों के संरक्षण के लिए वन विभाग लंबे समय से लगातार काम कर रहा है। 2025 की गणना के अनुसार, सेंचुरी में घड़ियालों की संख्या बढ़कर 2462 तक पहुंच गई है। जबकि सेंचुरी की स्थापना के बाद 1978-79 में चंबल नदी में 75 घड़ियाल छोड़े गए थे।

तुलना करें तो बिहार की गंडक नदी में लगभग 400 और नेपाल के कोसी (कटनकिया घाट) क्षेत्र में भी करीब 400 घड़ियाल ही हैं। इन नदियों की तुलना में चंबल नदी का वातावरण घड़ियालों के लिए सबसे अनुकूल साबित हुआ है, जहां उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है।

रिपोर्ट में खुलासा- मगरमच्छों के पेट में मिले ट्रांसमीटर- जलीय जीव विशेषज्ञ ज्योति प्रसाद दंडोतिया के अनुसार, चंबल सेंचुरी में घड़ियालों की संख्या जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए थी, वह नहीं बढ़ सकी। इसकी बड़ी वजह यह है कि चंबल में आने वाली बाढ़ के दौरान घड़ियालों के सिर्फ 3 प्रतिशत बच्चे ही जीवित रह पाते हैं।

इसके अलावा, वयस्क मगरमच्छ तीन साल तक के घड़ियालों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस बात का खुलासा एमसीबीटी (मद्रास क्रोकोडायल बैंक ट्रस्ट) की रिपोर्ट में भी हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान द्वारा चंबल नदी में छोड़े गए घड़ियालों पर रेडियो टेलीमेट्री ट्रांसमीटर लगाए गए थे। जब इनकी लोकेशन ट्रेस की गई, तो कई ट्रांसमीटर एडल्ट मगरमच्छों के पेट के भीतर पाए गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मगरमच्छ लगातार छोटे घड़ियालों पर हमला कर रहे हैं।

कुख्यात जुबैर मौलाना और साथी को तीन साल की सजा

डांसर युवती को बंधक बनाकर छेड़छाड़ की थी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कुख्यात अपराधी जुबैर मौलाना और उसके गुर्गे शुभम राय को भोपाल की एक कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने यह फैसला सुनाया है। दोनों ने डांसर युवती को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की थी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक राजेश सिंह द्वारा पैरवी की गई थी। भीम नगर जहांगीराबाद निवासी युवती विवाह समारोह में डांसर के रूप में काम करती है। वर्ष 2017 में वो एक विवाह समारोह में डांस कर रही थी।

बंधक बनाकर डांस करने को मजबूर किया- इसी दौरान कुख्यात अपराधी जुबैर मौलाना एवं उसके गुर्गों ने जान से मारने की धमकी देकर युवती को बंधक बनाकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरन डांस करने पर मजबूर किया था। युवती की शिकायत पर थाना जहांगीराबाद ने आरोपियों के खिलाफ धारा- 341,342, 354, 34, 506 भाग -2 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने मंत्रालय में म.प्र. राज्य पशु कल्याण सलाहकार मण्डल के साथ की बैठक।

बीजेपी के आईटी सेल वाले मोबाइल ऐप से ईसी करा रहा एसआईआर

- बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने छेड़ा नया संग्राम, एक तीर से दो निशाने

गंगासागर (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार (06 जनवरी) को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राज्य में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले में सागर द्वीप की अपनी दो दिवसीय यात्रा समाप्त करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने ईसी पर चुनावी सूची संशोधन करते समय सभी तरह की गलत चालें चलने का आरोप लगाया। ममता वहां

आगामी गंगासागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने गई थीं। मुख्यमंत्री बनर्जी ने आरोप लगाया, ईसी, एसआईआर कराने के लिए सभी तरह की गलत चालें चल रहा है। यह योग्य मतदाताओं को 'मृतक' के रूप में चिह्नित कर रहा है और बुजुर्गों,बीमारों को सुनवाई के लिए मजबूर कर रहा है।

'पाक फौज है तैयार' लश्कर-ए-तैयबा का 'गजवा-ए-हिंद' का ऐलान

- आतंकी सैफुल्ला सैफ ने खुले मंच से पीएम मोदी को दी धमकी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान में आतंकवादियों का बोलबाला है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'ओसिन टीवी' नाम के हैंडल से डाले गए वीडियो में लश्कर के बहावलपुर चीफ सैफुल्ला सैफ ने खुले मंच से भारत को धमकी दी है और 'गजवा-ए-हिंद' का आह्वान किया है। लश्कर के इस कुख्यात आतंकी ने न सिर्फ भारत के नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी की बल्की उन्हें काफिर भी बताया। इतना ही नहीं, इसने सारी हदें पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लेने की बात कही।

भारत के खिलाफ आतंकियों को उकसाया

सैकड़ों आतंकवादियों की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकी सैफुल्ला ने आतंकियों को उकसाते हुए कहा कि अब भारत के खिलाफ जिहाद का समय आ गया है। उसने हिंसा भड़काने वाले और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नेताओं की हत्या की खुली धमकी भी दे डाली। अपने जहरीले भाषण में सैफुल्ला ने दावा किया कि अब क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं

और बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसने भारत के खिलाफ गजवा-ए-हिंद का नारा बुलंद करते हुए दावा किया कि इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फौज भी तैयार है।

अलर्ट मोड पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां

लश्कर आतंकी का यह वीडियो सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के खुले मंच से दी गई धमकियां पाकिस्तान की उस हताशा को दर्शाती है, जो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ने के बाद महसूस कर रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप की हर धमकी का जवाब देने की जरूरत नहीं

- अमेरिका में मिला पीएम मोदी को सपोर्ट, सिंगर मैरी मिलबेन आई साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी सिंगर और भारत की प्रशंसक मानी जाने वाली मैरी मिलबेन ने यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणी पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे मित्र देश के साथ अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी आगे बढ़ते रहें और भारत के सर्वोत्तम हित में सेवा करना जारी रखें। मैरी मिलबेन ने इससे पहले राहुल गांधी की आलोचना करके

चर्चा में आ चुकी हैं। अब उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि यूएस राष्ट्रपति ट्रंप की हर धमकी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सिंगर मैरी मिलबेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप को रवैये के बारे में गलत सलाह दी जा रही है।

दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा

● पूजा के लिए उमड़ी भीड़, 17 जनवरी को की जाएगी स्थापना ● 5 नदियों के जल से अभिषेक और हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल

मोतिहारी (एजेंसी)। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पूर्वी चम्पारण के जानकीपुर में बन रहे विराट रामायण मंदिर पहुंच गया है। यहीं पर 17 जनवरी को 5 नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर, सोनपुर आदि के जल से शिवलिंग का अभिषेक होगा। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। इधर, सोमवार को विराट शिवलिंग जैसे ही पूर्वी चंपारण की धरती पर पहुंचा, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थापना से 12 दिन पहले श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का भव्य स्वागत किया। शिवलिंग को लेकर सबसे बड़ी चुनौती डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के रामपुर-खजुरिया ओवरब्रिज को पार करना रहा। इसे पार करने में पांच घंटे लग गए। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में भक्त घंटों पहले से सड़क किनारे खड़े होकर शिवलिंग के स्वागत का इंतजार करते नजर आए। डुमरिया घाट पुल पार करते ही चारों ओर हर-हर महादेव के

नारे गूंजे। जगह-जगह भव्य स्वागत द्वार बनाए गए थे, फूल-मालाओं और रोशनी से पूरे रास्ते को सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने ढोल-नगाड़ों और शंखनाद के साथ भगवान शिव का अभिनंदन किया। कई स्थानों पर शिवलिंग को कुछ देर के लिए रोका गया, जहां भक्तों ने विधिवत पूजा-अर्चना की और जयकारे लगाए। शिवलिंग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोतिहारी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। चकिया के एसीपी संतोष कुमार खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। उनके नेतृत्व में करीब 150 से अधिक पुलिस बल को तैनात किया गया है।

पीएम मोदी ट्रम्प के आगे क्यों झुक रहे ,दें जवाब

- खड़गे बोले-उन्हें सिर हिलाने के लिए पीएम नहीं चुना

कांग्रेस अध्यक्ष बोले-वेनेजुएला में बने हालात ठीक नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों को लेकर सोमवार को पीएम मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा- मैं नहीं समझ पा रहा कि मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं है। आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं चुना। दरअसल खड़गे का बयान ट्रम्प के दावे पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस से तेल आयात पर अमेरिकी

नाराजगी के बाद भारत ने तेल खरीद घटाई, क्योंकि मोदी मुझे (ट्रम्प) खुश करना चाहते थे। खड़गे ने वेनेजुएला की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा- वहां बन रहे हालात दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। डराने और विस्तारवादी नीति ज्यादा समय तक नहीं चलती। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग इतिहास बन चुके हैं। वैश्विक शांति बिगाड़ने वाली सोच ठीक नहीं है। खड़गे ने ट्रम्प के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें वे बार-बार शांति कराने की बात कहते हैं।

प्रैक्टिशनर के लिखने पर ही दवाइयों का विक्रय

इंदौर। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त ने इंदौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में चिन्हित दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार समस्त नाइट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाइट्रावेट टैबलेट), समस्त क्लोनाज़ेपम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टैबलेट, समस्त ऑक्साजेपाम टेबलेट्स, समस्त एटीजोलम टेबलेट, समस्त अल्प्राजोलम टेबलेट्स, समस्त कोडीन फॉस्फेट सिरप/टेबलेट, क्लोजापाम टेबलेट (फीजीयम टैबलेट आदि) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाए। गर्भपात संबंधित औषधियां जैसे रू486, माइफप्रिस्टोन एवं मिसोप्रोस्टल व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाओं (गोली, इंजेक्शन, जेल) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाएगा एवं लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा रखी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 1 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

चाइना डोर से पतंग उड़ाते युवक को पकड़ा

इंदौर। शहर के तीन थाना इलाकों में प्रतिबंधित चायना डोर को लेकर कार्रवाई की गई। अन्नपूर्णा में एक मैदान से चाइनीज धागे से पतंग उड़ाने के मामले में एक युवक को पकड़कर उस पर कार्रवाई की गई। वहीं उससे पूछताछ की जा रही है। वह इसे कहां से लेकर आया था। चाइनीस डोर बेचने वालों की दुकान को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अन्नपूर्णा पुलिस ने आशीष गोयल निवासी तापी परिसर को पकड़ा है। आरोपी प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहा था। अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे खाली मैदान से ही वह इससे पतंग उड़ा रहा था। जिसमें पुलिसकर्मियों ने उसे देखा तो थाने लेकर आए और उस पर 223 बीएनएस के चलते कार्रवाई की गई है। चंदन नगर पुलिस ने भी अय्यूब मंसूरी निवासी नंदन नगर नाले के पास को मदीना मस्जिद के पास से पकड़ा। उसके पास से 7 चाइनीज मांझे मिले हैं। वह इसे दुकान से बेच रहा था। पुलिस ने उसकी दुकान भी सील कर दी। वहीं द्वारकापुरी पुलिस ने भी वृंदावन चौरसिया को पकड़ा है। आरोपी के पास से 1 चाइनीज मांझा मिला है। सभी पर अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की गई है।

सुनार की दुकान से जेवरों से भरा बैग चोरी

इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र के हाट बाजार में जेवरात चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने एक सुनार की अस्थायी दुकान से चांदी के जेवरों से भरा बैग उड़ा लिया। घटना उस समय हुई, जब दुकानदार बैग मां के पास रखकर कुछ दूरी पर कार लेने गया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार जवाहर टेकरी, शंकर मंदिर के पास रहने वाले फरियादी राजेश कुमार सोनी (50) हर रविवार की तरह आम रोड पर पलंग और पन्नी बिछाकर चांदी की पायल, बिछिया, अंगूठी और कड़े आदि की दुकान लगाते हैं। रविवार शाम करीब 6.30 बजे वे अपनी मां कमला बाई के साथ दुकान समेट रहे थे। इस दौरान उन्होंने चांदी के जेवर एक बैग में रखकर मां को उसके पास खड़ा किया और स्वयं कार लेने चले गए। कुछ ही मिनटों में बदमाशों ने मौका देखकर बैग पर हाथ साफ कर दिया। वापस लौटने पर बैग गायब मिला। आसपास खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। चंदन नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परदेशीपुरा, एमआईजी पुलिस का साझा मार्च

इंदौर। शहर में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय कायम करने के उद्देश्य से सोमवार को थाना परदेशीपुरा एवं थाना एमआईजी पुलिस ने संयुक्त रूप से पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-2 अमरेंद्र सिंह तथा सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा हिमानी मिश्रा ने किया। मार्च के दौरान थाना प्रभारी परदेशीपुरा आरडी कानवा और थाना प्रभारी एमआईजी सीबी सिंह अपने-अपने बल के साथ मौजूद रहे। पुलिस दल ने एलआईजी कॉलोनी, अनूप नगर,अंबेडकर नगर,अटल द्वार, पाटनीपुरा,मालवा मिल की जूनी चाल,जनता क्वार्टर,नंदा नगर, तीन पुलिया और सर्वहारा नगर सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया। पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से संवाद कर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की।

'एसआईआर' में छूटे वोटरों के नाम जुड़े

इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची से दस्तावेजों के अभाव में छूटे मतदाताओं को अब राहत मिल रही है। खजराना क्षेत्र में ऐसे मतदाताओं के नाम पुनः जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) द्वारा संबंधित मतदाताओं की सुनवाई की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ताकि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकें। सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की वैधता की जांच की जा रही है। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उनके नाम मतदाता सूची में पुनः जोड़े जाएंगे। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। इस अभियान से बड़ी संख्या में मतदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पड़ोसी ने दिव्यांग युवती से हरकत की

इंदौर। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती के साथ पड़ोसी द्वारा गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार रात करीब 12.30 बजे की है। आरोपी ने युवती के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने समय रहते देख लिया। सूचना पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

होटल कर्मचारी की मौत- चंदन नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में 45 वर्षीय होटल कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जवाहर टेकरी पर दुर्गेश प्रसाद पुत्र रामचंद्र (45) निवासी मारुति पैलेस का शव रविवार को सड़क किनारे मिला था। शव का पोस्टमार्ट्म करवाया गया है।

अहमद के साथ होटल में मिली हिंदू युवती

इंदौर। पलासिया थाना क्षेत्र में निजी ट्रैवल्स में काम करने वाली एक युवती को कश्मीरी युवक के साथ होटल में देखा। सूचना मिलने पर बजरंग दल और पुलिस मौके पर पहुंची। बजरंग दल ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया और कड़ी कार्रवाई की बात कही। हालाकि युवती ने एफआईआर दर्ज करवाने से इंकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक इम्तियाज अहमद मलिक निवासी आजाद नगर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बताया कि वह मूल रूप से वह जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के बनेहाल का निवासी है।

'एशियन वॉटरबर्ड सर्वे 2026' में परिंदों की मौजूदगी से उम्मीद

19 जलस्रोतों के सर्वे से तालाबों की असलियत उजागर

इंदौर। जिले में 3 और 4 जनवरी को हुई 'एशियन वॉटरबर्ड सर्वे' (एडब्ल्यूसी) 2026 ने जिले के तालाबों और झीलों की पारिस्थितिकी सेहत का महत्वपूर्ण आकलन प्रस्तुत किया। वन विभाग के डीएफओ प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में हुए इस सर्वे में सामने आया कि जिले के कई जलस्रोत आज भी प्रवासी व स्थानीय जल पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय बने हैं। लेकिन, कुछ प्रमुख वेटलैंड पर बढ़ता मानवीय दबाव भविष्य के लिए गंभीर संकेत दे रहा है। डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि यह सर्वे केवल पक्षियों की गणना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल गुणवत्ता, जलीय वनस्पति, खुले जल क्षेत्र और मानवीय हस्तक्षेप जैसे पहलुओं का भी वैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया गया। इंदौर वन मंडल के अंतर्गत इस साल 19 तालाबों, झीलों और जलाशयों को सर्वे में शामिल किया गया, जिनमें सिरपुर झील, बिलावली तालाब, तलावली चांदा, काला कुंड, माचल जलाशय, लेक व्यू (महू) और यशवंत सागर प्रमुख रहे। इसके साथ ही मानपुर, चोरल और देपालपुर क्षेत्र के ग्रामीण व वन सीमा से जुड़े जलस्रोतों का भी आकलन किया गया। सर्वे के दौरान गर्गेनी, नॉर्दर्न शोवलर, रुडी शेलडक, एशियन ओपन बिल, सारस, ग्रेट कार्मोरेंट, रिवर टर्न, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, पर्पल हेरॉन और किंगफिशर जैसी अनेक प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई। मांगली तालाब, मांडव देव और नखेरी डैम में पक्षियों की अच्छी संख्या ने यह स्पष्ट किया कि जहां जल, वनस्पति और मानवीय गतिविधियों में संतुलन है, वहां जैव विविधता संरक्षित रहती है।

यशवंत सागर और चोरल क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक पाई गई। जबकि, सिरपुर झील में जलकुंभी का अत्यधिक फैलाव, खुले पानी की कमी और लगातार बढ़ती मानवीय गतिविधियां चिंता का विषय बनीं। सर्वे में 50 से अधिक प्रशिक्षित पक्षी प्रेमियों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सभी आंकड़े ई-बर्ड ऐप पर दर्ज किए गए हैं, जिनके आधार पर इंदौर जिले की विस्तृत प्रिंट और डिजिटल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डीएफओ प्रदीप मिश्रा के अनुसार, इंदौर के तालाब आज भी जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए सतत निगरानी, सुधारात्मक कार्य और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

भागीरथपुरा में पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं का कलेक्टर, निगम आयुक्त ने जायजा लिया

व्यवस्थाओं को लेकर पूरे इलाके को 32 बीटों में विभाजित किया गया

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा एवं नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जिला प्रशासन और नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भागीरथपुरा क्षेत्र में की जा रही पेयजल टैंकर व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान भागीरथपुरा क्षेत्र के प्रभावित स्थलों पर पेयजल टैंकरों की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था, संजीवनी क्लीनिक के माध्यम से उपचार, नागरिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री वर्मा एवं निगम आयुक्त श्री सिंघल द्वारा समस्त अपर आयुक्तों, विभागीय अधिकारियों एवं एनजीओ टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बताया गया कि झोन क्रमांक 04 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 स्थित भागीरथपुरा क्षेत्र में जल वितरण की पर प्रभावी नियंत्रण हेतु संपूर्ण क्षेत्र को 32 बीटों में विभाजित किया गया है।

इन बीटों के माध्यम से जल वितरण पर नियंत्रण, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक सफाई अभियान की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है।

उक्त 32 बीटों में की जाने वाली कार्यवाहियों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु अपर आयुक्त प्रखर सिंह, अर्थ जैन, आकाश सिंह, आशीष पाठक, अभय राजनगांवकर, मनोज पाठक, श्रृंगार श्रीवास्तव एवं नरेंद्र नाथ पांडे को आवंटित बीट क्षेत्रों में संपूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है। संबंधित अपर आयुक्त अपने आवंटित बीट क्षेत्रों में प्रतिदिन निरंतर भ्रमण करते हुए नागरिकों से समन्वय स्थापित करेंगे और उनके द्वारा पेयजल, सफाई एवं उपचार से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही दिन-प्रतिदिन की प्रगति एवं स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से अवगत करायेंगे। कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में वर्तमान में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

भागीरथपुरा जल त्रासदी में 17वीं मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम

इंदौर के अस्पतालों में अब भी करीब 150 मरीज भर्ती

इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से उपजे स्वास्थ्य संकट ने एक और जान ले ली। इलाज के दौरान एक रिटायर्ड मिलिट्री वाले की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। क्षेत्र में सैकड़ों लोग अब भी उल्टी-दस्त और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, जबकि प्रशासन के बेहतर इलाज के दावे जमीन पर खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। मृतक की पहचान ओमप्रकाश शर्मा (69) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से धार जिले की शिव विहार कॉलोनी के निवासी थे। वे अपने बेटे और परिजनों से मिलने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल रोड पर आए थे। 1 जनवरी को अचानक उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत बिगड़ने पर 2 जनवरी को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और बाद में वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की हालत गंभीर होने के पीछे किडनी पर असर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे और किडनी संबंधी समस्या की पुष्टि नहीं की गई है। इधर, भागीरथपुरा में हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार फिलहाल करीब 150 मरीज विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। क्षेत्र में अब भी उल्टी-दस्त और पेट संबंधी बीमारियों के नए मामले सामने आ रहे हैं। लगातार हो रही मौतों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और पेयजल आपूर्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इंदौर एयरपोर्ट पर बैठने, चार्जिंग पॉइंट की समस्या, यात्री बीमार

यात्री सुविधाओं के मामले में इंदौर एयरपोर्ट सबसे खराब

इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को लेकर यात्रियों की शिकायत एक बार फिर सामने आई है। वेटिंग एरिया में पर्याप्त कुर्सियां नहीं होने और चार्जिंग पॉइंट्स खराब होने को लेकर यात्रियों ने नाराजगी जताई। इंदौर से यात्रा कर रहे एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शिकायत करते हुए लिखा कि यात्री सुविधाओं के मामले में इंदौर एयरपोर्ट सबसे खराब एयरपोर्ट्स में शामिल है। यात्री एस लखोटिया ने लिखा कि गेट नंबर 10 और 11 पर चार्जिंग सॉकेट कम हैं। बैठने के लिए कुर्सियां भी पर्याप्त नहीं हैं। यात्री ने एयरपोर्ट की तुलना बस स्टैंड से कर दी। इस पर एयरपोर्ट प्रबंधन ने जवाब देते हुए माफी मांगी और कहा कि टर्मिनल पर कार्य चल रहा है। जल्द ही कुर्सियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्री का कहना है कि उड़ानों में देरी के दौरान लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। मोबाइल चार्जिंग व कुर्सियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। यात्रियों ने मांग की है कि सुविधाओं में जल्द सुधार किया जाए।

महिला यात्री एयरपोर्ट पर बेहोश- रविवार को लगातार दूसरे दिन मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई। इंदौर से दिल्ली जा रही एक महिला यात्री अचानक एयरपोर्ट पर बेहोश हो गई। एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा गया। इंडिगो एयरलाइंस की दोपहर 1.30 बजे इंदौर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट (6ई-6609) से दिल्ली जाने के लिए 66 वर्षीय महिला यात्री परवीन सिंगला पति विनोद सिंह एयरपोर्ट पहुंची। वे फ्लाइट में जाने के लिए चेक-इन करते हुए सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जा चुकी थीं। बोर्डिंग से कुछ समय पहले यहीं अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे बेहोश हो गईं। इस पर तुरंत एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल इमरजेंसी रूम से डॉक्टर ने आकर उनकी जांच की। डॉक्टर के मुताबिक उनकी ब्लड शुगर कम पाई गई। बेहतर उपचार के लिए उन्हें तुरंत एयरपोर्ट की एम्बुलेंस द्वारा नजदीकी अस्पताल में भेजा गया।

बुजुर्ग महिला को डिजिटली अरेस्ट किया रुपए भेजने बैंक गईं, मैनेजर ने बचाया

महिला पर बैंक जाकर 4 लाख रु आरटीजीएस करने का दबाव बनाया

इंदौर। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसकी बेटी और बेटे की सूझबूझ ने डिजिटल अरेस्ट से होने वाली ठगी का शिकार होने से बचा लिया गया। ठगों ने खुद को अधिकारी बताकर महिला को डराया और 4 लाख रुपए ट्रांसफर कराने की कोशिश की थी। स्टेट साइबर सेल के डीएसपी नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि कनाडिया क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ रहती हैं। शनिवार को बेटी के घर से बाहर जाने के बाद महिला के पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उसने कहा कि महिला के बैंक खाते में 6 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी मिली है और इसी मामले में अब आपकी गिरफ्तारी होगी। नकली अधिकारी ने महिला को किसी से भी बात न करने की हिदायत दी और कॉल डिस्कनेक्ट न करने का दबाव बनाया। इसके बाद उसने महिला से एटीएम कार्ड की जानकारी मांगी। महिला ने बताया कि एटीएम कार्ड उनकी बेटी के पास रहता है।

एटीएम कार्ड का फोटो मांगा

इसके बाद आरोपी ने बेटी के एटीएम कार्ड का फोटो भेजने को कहा। बेटी मीटिंग में होने के कारण कुछ देर बाद भेजने की बात कहने लगी। जब उसने फोटो मांगने का कारण पूछा तो बुजुर्ग महिला ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। इसके बाद नकली सीबीआई अफसर ने महिला पर बैंक जाकर 4 लाख रुपये आरटीजीएस करने का दबाव बनाया। साथ ही कहा कि अगर किसी को बताया तो मामला और बिगड़ जाएगा। आरोपी ने महिला से मोबाइल चालू रखने और बैग में रखने के लिए कहा। बैंक पहुंचकर बुजुर्ग महिला ने मैनेजर से 4 लाख रुपए ट्रांसफर करने की मांग की।

बैंक मैनेजर की सतर्कता

बुजुर्ग महिला के बेटे के किसी अन्य बैंक में बड़े पद पर होने की जानकारी होने पर बैंक मैनेजर को शक हुआ। मैनेजर ने तुरंत महिला के बेटे से संपर्क किया। बेटे ने पैसे ट्रांसफर करने से साफ मना कर दिया और बहन से बात की। इसके बाद परिवार ने स्टेट साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।

मौके पर पहुंची साइबर पुलिस - शिकायत मिलते ही स्टेट साइबर सेल की टीआई अंजू पटेल तत्काल बुजुर्ग महिला के पास पहुंचीं। उन्होंने महिला का मोबाइल लेकर व्हाट्सएप कॉल पर फर्जी सीबीआई अफसर से बात की। पुलिस की आवाज सुनते ही आरोपी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। टीआई अंजू पटेल ने आरोपी का नंबर ब्लॉक करवाया और एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बुजुर्ग महिला को सुरक्षित घर पहुंचाया गया और परिवार के साथ काउंसलिंग भी की गई। इस तरह समय रहते कार्रवाई से 4 लाख रुपए की ठगी होने से बचा लिया।

बसों में अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं 7 बसें जब्त, परमिट होंगे निरस्त

नियम का पालन न करने पर आरटीओ ने कार्रवाई की

इंदौर। यात्री वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर परिवहन विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सोमवार को आरटीओ की टीम द्वारा तीन इमली बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में फायर मानकों और आपातकालीन निकास के इंतजाम को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 7 बसें जब्त की गईं। इनमें 3 स्लीपर कोच बसें शामिल हैं। गंभीर सुरक्षा खामियां पाई जाने वाली बसों के परमिट निरस्त किए जा रहे है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि इन बसों में अग्नि सुरक्षा उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट और पंजीयन के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता का पालन नहीं किया गया था। इसके चलते संबंधित स्लीपर कोच बसों के पंजीयन, फिटनेस और परमिट निरस्त करने के लिए मूल पंजीयन प्राधिकारी और संबंधित आरटीओ को पत्र लिखा जा रहा है। वहीं एक बस बिना वैध परमिट के संचालन करते हुए पाई गई, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया। जबकि एक बस का फिटनेस निरस्त किया गया। निरीक्षण के दौरान पंजीयन और परमिट के अनुसार निर्धारित बैठक क्षमता में भी विसंगति पाई गई। इस आधार पर संबंधित बसों के पंजीयन और परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यहजांच अभियान एआरटीओ राजेश गुप्ता के नेतृत्व में परिवहन विभाग के स्टाफ और विशेष जांच दल द्वारा चलाया जा रहा है, जो आगे भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा।

यह है अग्नि सुरक्षा मानक

परिवहन विभाग के अनुसार एक अक्टूबर 2023 के बाद पंजीकृत डीलक्स बसों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम तथा डीलक्स बसों और स्कूली वाहनों में फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम अनिवार्य किया गया है। जबकि, एक अक्टूबर 2023 से पहले पंजीकृत वाहनों में निर्धारित वजन का सीजफायर, तय संख्या में इमरजेंसी एग्जिट और आपात स्थिति में कांच तोड़ने के लिए हैमर होना अनिवार्य है।

कमर्शियल सिलेंडरों का व्यावसायिक व घरेलू सिलेंडरों का अवैध उपयोग

महू और देपालपुर क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठानों से 40 सिलेंडर जब्त

इंदौर। बगैर कनेक्शन के कमर्शियल सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में जिले के महू और देपालपुर क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 40 सिलेंडर जब्त किए गए। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि खाद्य विभाग के दो अलग-अलग जांच दल द्वारा घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण, अवैध व्यावसायिक घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्यवाही की गई। इस क्रम में बालाजी चौराहा बेटमा, देपालपुर में इंडियन ढाबा के संचालक देवी सिंह से 3 गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम, बालाजी रेस्टोरेंट के संचालक नीलेश मोदी से 3 गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम क्षमता के व्यावसायिक दुरुपयोग में जब्त किए गए। द्वितीय जांच दल द्वारा महू में कार्रवाई करते हुए दस्तूर ढाबा महू के संचालक हेमंत वर्मा से 19 किग्रा क्षमता के 8 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर बिना कनेक्शन के उपयोग करने पर जब्त किए गए। इसी तरह बिना कनेक्शन के उपयोग करने पर वृन्दावन फैमिली रेस्टोरेंट महू-पीथमपुर रोड के संचालक बॉबी वर्मा से 3 नग, माँ वैष्णव ढाबा मानपुर रोड के संचालक सचिन सिंह से 12 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसी प्रकार राजपूत ढाबा एंड रेस्टोरेंट एबी रोड़ पर संचालक महेन्द्र राजपूत,रोहित चौहान से11 नग व्यावसायिक गैस सिलिंडर इण्डेन के जप्त किए गए।

इस कार्रवाई में 40 गैस सिलेंडरों की जब्ती की गई। मारू ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वह घरेलू सिलेंडर का उपयोग नहीं करें। व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग अधिकृत गैस एजेंसीसे कनेक्शन एस वी प्राप्त कर हीकरें। गैस सिलेंडर रिफिल, अवैध कारोबार, भंडारण अवैध उपयोग,अवैध क्रय-विक्रय के विरूद्ध चल रहा अभियान निरंतर जारी रहेगा।

संपादकीय

फिर खेल में राजनीति...

पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों में तनाव अब खेल तक आन पहुंचा है। बीसीसीआई के निर्देश पर शाहरुख खान की कंपनी केकेआर द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर निकालने के बाद बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा कि अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम टी 20 वर्ल्ड के अपने मैच भारत में नहीं खेलेगी। इस पर आईसीसी का क्या फैसला लेता है, यह देखने की बात है। लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्ते अब और नीचे चले गए हैं। बांग्लादेश के युवा और खेल मामलों के सलाहकार आसिफ़ नज़रुल ने कहा था कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों और देश का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुलामी के दिन ख़त्म हो गए हैं। एक बयान में आसिफ़ नज़रुल ने आरोप लगाया था कि बीसीसीआई ने 'चरमपंथी सांप्रदायिक समूहों के दबाव में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से हटाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि इस बार आईपीएल में शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी तेज गेंदबाज मुस्तफ़िज़ुर रहमान को 9.2 करोड़ रू. में खरीदा था। लेकिन हाल में बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या के बाद कई हिंदू संतों और संगठनों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाने पर कड़ा ऐतराज किया था। रहमान को लेने के लिए शाहरुख खान को टारगेट कर उन्हें 'गद्दार' तक कहा गया। हालांकि बांग्लादेश के घटनाक्रम का क्रिकेट से सीधा कोई रिश्ता नहीं है। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से कहा है कि वह इस साल फरवरी में होने वाले टी 20 वर्ल्ड कप के उसके मैच श्रीलंका में कराए। यह वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान के भारत के साथ सभी मैच भी श्रीलंका में होने हैं। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश का पहला मैच ओपनिंग डे पर वेस्टइंडीज से कोलकाता में होना है। उधर मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अगर वे मुझे जाने देंगे, तो मैं क्या करूँगा? भारत में भी बीसीसीआई के फ़ैसले के बाद इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि खेल को राजनीतिक तनाव से अलग रखा जाना चाहिए। वहीं इतिहासकार रामचंद्र गुहा का मानना है कि ये नासमझी भरा फ़ैसला है और इसकी वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। हालांकि बीजेपी नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई के इस फ़ैसले का स्वागत किया है। दूसरे, एमआई एमिरेट्स टी20 लीग में अंबानी की टीम में एक और मशहूर बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिब अल हसन खेल रहे हैं और शाकिब को अभी तक टीम से नहीं हटाया गया है। तो क्या बीसीसीआई में हिंदूवादी कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया। अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं लेना था तो नीलामी के पहले वैसे निर्देश दिए जाने चाहिए थे। सवाल भारत सरकार पर भी उठ रहे हैं। हाल में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में बांग्लादेश गए और श्रद्धांजलि देकर एक सकारात्मक कूटनीतिक पहल की। लेकिन रहमान को टीम से बाहर करने से बात फिर वहीं जा पहुंची है। इसी बात का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा कि इस मामले में मुस्तफ़िज़ुर रहमान, शाहरुख खान और केकेआर को निशाना बनाया गया है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी कहा कि एक फ्रेंचाइजी और उसके मालिक को सवाल करने का क्या मतलब है। ये नियम बीसीसीआई ने बनाया है। कोई बीसीसीआई, आईसीसी और गृह मंत्रालय पर सवाल क्यों नहीं कर रहा है।

अमेरिकी नव उपनिवेशवाद का ताजा शिकार वेनेजुएला

नजरिया

डॉ. सुधीर सक्सेना
लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अमेरिकी सेना ने मुहिम को इस खूबी से संचालित किया कि किसी को पेशगी भनक भी न लगी। वेनेजुएला के सुरक्षा-बल कोई प्रतिरोध नहीं कर सके और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस के साथ-डेल्टा फोर्स के हत्थे चढ़ गये। वह राजधानी काराकास में सैनिक अड्डे में पत्नी के साथ निश्चिंत सो रहे थे कि अमेरिका के फौजी जवानों ने उन्हें दबोच लिया। मादुरो ने नजदीकी इस्पाती कक्ष में भागने की कोशिश कीं, किंतु असफल रहे। उन्हें बलात खींचते हुये बाहर ले जाया गया। उन्हें हथकड़िया पहनाई गयी और आँखों पर पट्टी बाँध दी गई। कुछ ही घंटों बाद वह अमेरिका में थे। इस दशा में वह लोअर मैनहट्टन में थे और उपस्थित जनों को 'गुडनाइट' और 'हैप्पी न्यू इयर' कहते पाये गये।

सब कुछ आईने की मानिंद साफ है। कहीं कुछ भी कुहरिल या गोपन नहीं। वेनेजुएला में तीन जनवरी शनिवार की स्याह सर्द रात में जो कुछ हुआ वह अमेरिकी नव उपनिवेशवाद का ऐसा खूंखार आक्रामक चेहरा है जिस पर निर्लज्ता का लेप नजर आता है। भूमिका बरसों से बन रही थी, किंतु यह अंदेशा कतई नहीं था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर अमेरिकी डेल्टा फोर्स काराकास में 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' को इस तरह अंजाम देंगे। अमेरिकी सेना ने मुहिम को इस खूबी से संचालित किया कि किसी को पेशगी भनक भी न लगी। वेनेजुएला के सुरक्षा-बल कोई प्रतिरोध नहीं कर सके और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस के साथ-डेल्टा फोर्स के हत्थे चढ़ गये। वह राजधानी काराकास में सैनिक अड्डे में पत्नी के साथ निश्चिंत सो रहे थे कि अमेरिका के फौजी जवानों ने उन्हें दबोच लिया। मादुरो ने नजदीकी इस्पाती कक्ष में भागने की कोशिश कीं, किंतु असफल रहे। उन्हें बलात खींचते हुये बाहर ले जाया गया। उन्हें हथकड़िया पहनाई गयी और आँखों पर पट्टी बाँध दी गई। कुछ ही घंटों बाद वह अमेरिका में थे। इस दशा में वह लोअर मैनहट्टन में थे और उपस्थित जनों को 'गुडनाइट' और 'हैप्पी न्यू इयर' कहते पाये गये। अमेरिकी डिटेंशन सेंटर में रखे गये मादुरो पर अब मादक पदार्थों की तस्करी व अन्य अपराधों के लिये अमेरिकी कानून के तहत मुकदा चलेगा। इस मुकदमे के फैसले का अनुमान लगाना कठिन नहीं है।

अमेरिकी सेना को इस आक्रामक कार्रवाई के पूरा करने में बमुश्किल तीस मिनट लगे। जिस टुकड़ी ने इसे संपन्न किया, उसे फौज की एलीट टुकड़ी माना जाता है। इस कथित भद्र टुकड़ी ने पिछली लगभग एक छमाही में खूब तैयारी और अभ्यास किया। मादुरो क्या खाते हैं कहाँ जाते हैं और क्या पहनते हैं, यहाँ तक कि उनके पेटस (कुत्तों) की गतिविधियों की राई रत्ती जानकारी जुटाई गयी। रिहर्सल के लिये उनके ठिकाने की अनुकृति तैयार की गयी और चाक-चौबंद इंतजाम के बाद मिशन को अंजाम दिया गया। इस अभियान में अमेरिका ने आधुनिकतम अपाचे हेलीकाप्टरों का भी इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि अपाचे के साथ प्रतिरोध का ऐतिहासिक जनजातीय संदर्भ जुड़ा हुआ है। यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि अमेरिका को अपनी आक्रामक सैन्य कार्रवाई में किसी प्रतिरोध का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? अमेरिकी पाबंदियों और ट्रंप की चेतावनियों के परिप्रेक्ष्य में मादुरो को सजग और सन्नद्ध रहना था। क्या वह ट्रंप के अंतिमेत्थम को घड़की मान रहे थे? वह अपनी सुरक्षित मांद में होते तो उन्हें दबोचना मुश्किल था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मादुरो ने सन् 2013 में शावेज के उत्तराधिकारी के तौर पर सत्ता संभाली थी, घरेलू और वैदेशिक नीति में वह शावेज के नक्शे पर चले। उन्होंने खुद तेल भंडारों का दोहन करना चाहा, जिन पर वाशिंगटन की अर्से से गिद्ध दृष्टि है। सन् 2018 और सन् 2024 के आम चुनावों में उन पर 'वोट चोरी'के गंभीर आरोप लगे। अमेरिका और योरोपीय देशों समेत घरेलू विपक्ष ने माना कि मादुरो चुनावी धांधली से फिर से सत्ता में आये हैं। अमेरिका ने उन पर खुल्लमखुल्ला नारको-टेररिज्म का आरोप लगाया और कहा कि मादुरो ड्रग कार्टेल का संचालन कर रहे हैं। कार्टेल डेलॉस सोल्स के संचालन और अन्य आरोपों से बिंधे मादुरो को असफल कू-दे-ता, विरोध प्रदर्शनों, धांधली के आरोपों, आर्थिक पाबंदियों आदि का सामना करना पड़ा। इस बीच वेनेजुएला में मुद्रा स्फीति की दर, मंहगाई और गरीबी बढ़ती गयी। जब-तब तेल निर्यात से उसे राहत मिली। वह तेल की बदौलत भयावह संकट से उबर भी जाता, लेकिन ट्रंप ने मादुरो की मुश्कें कसने की कसम खा रखी थी। अमेरिका ने रणनीति के तहत एंटी-ड्रग्स मुहीम छेड़ी, शैडो-फ्लीट पर पाबंदी लगा दी, तीस नौकायें नष्ट कर दीं और बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी। मादुरो पर पहले 15 मिलियन डालर का ईनाम था, जो ट्रंप के पुनः सत्ता में आने पर 25 मिलियन डॉलर और हाल में बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर कर दिया गया। यह एक बड़ी रकम है। इसके लोभ में लगता है कि मादुरो के प्रहरी और अंगरक्षक उनका साथ छोड़ गये। अंततः उनका हश्र भी कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन सरीखा हुआ। वह जीते जी दुश्मन के हाथ लग गये।

दो करोड़ 85 लाख की आबादी का वेनेजुएला खनिज और तेल समृद्ध लातिनी अमेरिकी राष्ट्र है। तेल के अथाह भंडार के अलावा वहां लोहा, कोयले, सोने, हीरे और निकिल के बड़े भंडार है। पूर्व गुआना, ब्राजील और कोलंबिया से घिरे वेनेजुएला एंजेल समेत असंख्य सुंदर प्रपातों, वर्षा वन, सुरम्य उद्यानों, कदाटुंबा में बिजली उत्पादन और मेरिडा में सर्वोच्च केबल कार के लिये जाना जाता है। सन 2025 के लिये शांति का नोबेल पुरस्कार भी यहां की मारिया कोरिना मचाडो को मिला। ट्रंप इस पुरस्कार के प्रबंल दावेदार थे, लेकिन मचाडो ने उन्हें पछाड़कर बाजी मार ली। मचाडो मादुरो की प्रबल विरोधी हैं और उन्होंने अमेरिका से सैन्य हस्तक्षेप की बात भी की थी। नोबेल पुरस्कार के लिये वह बाहरी मदद से चुपचाप चोरी छिपे वेनेजुएला से निकलकर ओस्लो पहुंच गयी बताई जाती है।

इस बात में शक नहीं कि शेखीखोर ट्रंप के तेवर तीखे हैं। मादुरो को सबक सिखाने के बाद उनकी घुड़कियों का महत्व बढ़ गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वेनेजुएला में वही होगा, जो वह चाहेंगे। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति सुश्री डेल्सी रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति होंगी, लेकिन ट्रंप ने सुरक्षित, सही और न्यायपूर्ण सत्ता हस्तांतरण तक सत्ता हाथ में रखने की बात कही है। यानि अब संसाधन समृद्ध वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका का उपनिवेश है। अमेरिका की विराट तेल कंपनियां वेनेजुएला में तेल उलीचेंगी और अनापशनाप मुनाफा बटोरेंगी। ट्रंप ने सेक्रेट्री ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत पर संतोष व्यक्त किया है। ट्रंप की दिक्कत यह है कि उनके देश में ही उनका विरोध हो रहा है। न्यूयार्क के मेयर ममदानी ने इस आक्रामक कार्रवाई का खुला विरोध किया है। रूस, चीन, ब्राजील, ईरान, क्यूबा, स्पेन, बेलिविया, चीले और कोलंबिया ने ट्रंप की निंदा की है, जबकि भारत ने पक्ष-विपक्ष में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। समूचे विश्व में इसे दादागिरी और अंतराष्ट्रीय नियमों और राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन माना जा रहा है। इसमें शक नहीं कि चीले, बोलीविया, डोमीनिकन रिपब्लिकन, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, हैती, मेक्सिको, पनामा और निकारागुआ में हस्तक्षेप और तख्तापलट के बाद उसकी दाढ़ से खून लग गया है। अब सबकी नजर यूं तो पांच जनवरी को सुरक्षा परिषद की बैठक पर है, अलबत्ता यह सच है कि वेनेजुएला का प्रसंग खूँखार अमेरिकी नव-उपनिवेशवाद की ताजा कड़ी है।

जल-विभीषिका एवं भविष्य का 'रिस्पांस ब्लूप्रिंट'

भागीरथपुरा

डॉ. तेज प्रकाश पूर्णानन्द व्यास
लेखक स्तंभकार हैं।

भागीरथपुरा जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जब प्रशासन और सिस्टम की विफलता के कारण मौतें होने लगें, तो 'सामान्य राहत' के बजाय 'वॉर-फुटिंग' (युद्ध स्तर) पर निम्नलिखित प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए थे : 1. 'ज़ोनिंग' एवं 'सोर्स कंट्रोल' (तत्काल प्रभाव से) जैसे ही क्षेत्र में 5 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आएं, प्रशासन को बिना किसी 'डेथ ऑडिट' या रिपोर्ट का इंतज़ार किए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए थे-

आइसोलेशन ऑफ पाइपलाइनः प्रभावित क्षेत्र की मुख्य पेयजल पाइपलाइन को तत्काल 'कट-ऑफ' किया जाना था। भागीरथपुरा में देरी का मुख्य कारण यही था कि अधिकारी 'लीकेज' ढूंढते रहे और लोग ज़हर पीते रहे। रेड ज़ोन घोषणाः प्रभावित 2-3 किलोमीटर के दायरे को 'संक्रमित क्षेत्र' घोषित कर वहां के सभी सार्वजनिक नलों और हैंडपंपों को सील किया जाना चाहिए था।

अल्टरनेटिव सप्लाईः केवल प्रमाणित और क्लोरिनेटेड वाटर टैंकर्स के माध्यम से पानी की आपूर्ति होनी थी , जिनकी निगरानी स्वयं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने करनी थी।

2. 'एक्टिव केस फाइंडिंग' एवं 'ट्राइएज' (डोर-टू-डोर सर्विलांस) अस्पताल आने वाले मरीजों का इंतज़ार करना मूर्खता है। प्रशासन को जनता के पास तत्काल जाना था-

रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी): प्रत्येक 10 घरों पर एक आशा कार्यकर्ता और एक पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती होनी थी। घर-घर जाकर तत्काल यह जांचे की जानी थी कि क्या किसी को हल्की मितली या दस्त है। प्रोफाइलैक्सिस वितरणः बिना किसी देरी के हर घर में 5 पैकेट ओआरएस, जिंक की गोलियां और 'क्लोरीन टैबलेट्स' का तत्काल वितरण अनिवार्य होना था। ट्राइएज सेंटरः क्षेत्र के भीतर ही एक अस्थाई 'स्टेबलाइजेशन सेंटर' तत्काल बनाना था, जहाँ गंभीर रूप से निर्जलित (डिहाईड्रेटेड) मरीजों को बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने से पहले तत्काल आईवी फ्लूइड दिया जाना था। भागीरथपुरा में एम्बुलेंस की देरी ने भी जानें ली हैं।

3. 'पॉइंट-ऑफ-यूज़' (पीओयू) जल शुद्धिकरण प्रोटोकॉल जब पाइपलाइनें 'कल्चर मीडिया' बन जाएं, तो केवल पानी उबालना पर्याप्त नहीं होताः शॉक क्लोरिनेशनः क्षेत्र के सभी भूमिगत टैंकों और ओवरहेड टैंकों में हाई-डोज़ क्लोरिनेशन किया जाना था। रेसिड्यूअल क्लोरीन टेस्टः हर 2 घंटे में क्षेत्र के 10 अलग-अलग बिंदुओं से पानी के सैंपल लेकर 'ओर्थो-टोलुडीन' (ओटी) टेस्ट किया जाना था। यदि मान 0.5 एमजी/लीटर से कम है, तो पानी को 'असुरक्षित' श्रेणी में रखकर वितरण रोका जाना था।

कंटेनर सैनिटाइजेशनः लोगों को पुराने भरे हुए पानी को फेंकने और बर्तनों को ब्लीचिंग पाउडर से धोने के निर्देश दिए जाने थे। 4. 'एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग' एवं 'सीवरेज इंटरवेंशन' भागीरथपुरा त्रासदी का मूल कारण 'क्रॉस-कंटेमिनेशन' थाः वैक्यूम सक्शनः क्षेत्र की सभी सीवर लाइनों को वैक्यूम पंपों से खाली किया जाना था ताकि पेयजल पाइपलाइनों पर पड़ने वाला बाहरी दबाव (इनफिल्टरेशन प्रेशर) कम किया जा सकता था। डाइ-ट्रेसर टेस्टः पाइपलाइनों में सुरक्षित रंगीन डाई डालकर यह पता लगाया जा सकता था कि रिसाव कहाँ से हो रहा है। यह तकनीक समय बचाती है और खुदाई के बिना लीकेज पकड़ती भी है।

केमिकल बैरियरः खुली नालियों और जलभराव वाले क्षेत्रों में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सघन छिड़काव हो ताकि मक्खियों और अन्य वाहकों द्वारा संक्रमण न फैले। 5. वैज्ञानिक सूचना संप्रेषण (रिस्क कम्यनिकेशन) भ्रम और डर संक्रमण से ज्यादा घातक होते हैंः वैधानिक चेतावनीः 'नल का पानी मौत का कारण बन सकता है' - ऐसी स्पष्ट चेतावनी लाउडस्पीकरों पर 30-30 मिनट के अंतराल पर दी जानी थी। सिम्पटम अलर्टः जनता को बताया जाए कि 'चावल के पानी जैसे दस्त' (राइस वाटर स्टूल) हैजा के लक्षण हैं और इसे सामान्य न समझें। अफवाह नियंत्रणः सोशल मीडिया पर फैल रही 'घरेलू नुस्खों' की अफवाहों को रोककर केवल वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को प्रसारित किया जाए। 6. पोस्ट-डिजास्टर 'जीनोम सीक्वेंसिंग' एक वैज्ञानिक के रूप में, यह प्रोटोकॉल तब तक अधूरा है जब तक हम 'पैथोजन' के स्ट्रेन को न पहचान लें-

जल-विभीषिका - 2026 पर श्वेत पत्र

कार्यकारी सारांश

यह श्वेत-पत्र एक ऐसी त्रासदी का विश्लेषण है जिसे टाला जा सकता था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर (भागीरथपुरा) में दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2926 के प्रथम सप्ताह तक पेयजल आपूर्ति में मल-मूत्र (सिवेज) के मिश्रण से 17 नागरिकों की अकारण मृत्यु हुई। यह रिपोर्ट वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करती है कि यह केवल एक प्राकृतिक प्रकोप नहीं, बल्कि 'इंजीनियरिंग विफलता' और 'प्रशासनिक भ्रष्टाचार' का परिणाम है।

वैज्ञानिक साक्ष्य और पैथोलॉजिकल विश्लेषणः

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के डेटा विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए हैं-

फेकल कोलिफॉर्म का तांडवः पेयजल के नमूनों में ई कोली और विब्रियो कोलेरी की उपस्थिति 'अनकाउंटेबल' श्रेणी में पाई गई। वैज्ञानिक दृष्टि से, पेयजल और सीवरेज लाइनों के बीच 'क्रॉस-कंटेमिनेशन' तब होता है जब दबाव के अंतर के कारण दूषित जल पेयजल पाइपलाइन के छिद्रों से भीतर प्रवेश करता है।

मृत्यु का कारणः आधिकारिक तौर पर इसे 'एक्यूट डायरिया' कहा गया, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह 'सेप्टिक शॉक' और 'हाइपोवोलेमिक शॉक' का मामला है, जहाँ दूषित जल के कारण शरीर का इलेक्ट्रोलाइट संतुलन 4-8 घंटों में बिगड़ गया और मल्टी-ऑर्गन फेलियर से मौतें 17 मौतें हुई। करोड़ों के निवेश के बावजूद यह त्रासदी क्यों हुई?

अमृत योजना और स्मार्ट सिटी का खोखलापनः अरबों रुपये सौंदर्यीकरण और ऊपर चमकते फुटपाथों पर खर्च किए गए, लेकिन जमीन के नीचे का 'यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर' साल पुराना और जर्जर है।

निगरानी का अभावः पानी के लीकेज का पता लगाने के लिए आधुनिक सेंसर तकनीक का अभाव। प्रशासनिक पर्दापोशः डेथ ऑडिट के नाम पर मौतों को 'पुरानी बीमारी' बताकर सरकारी आंकड़ों को छिपाना, ठीक वैसा ही जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के दौरान किया गया था।

आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉलः किसी भी सघन क्षेत्र में महामारी फैलने पर निम्नलिखित 'प्रोटोकॉल'

अनिवार्य किया जाना चाहिए-

अ. तत्काल अलगावः

संक्रमित जल स्रोत को 10 मिनट के भीतर बंद कर 'रेड जोन' घोषित करना।

वैकल्पिक टैंकर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

ब. सक्रिय निगरानीः

आशा और पैरामेडिकल टीमों द्वारा 'डोर-टू-डोर' स्कैनिंग। घर-घर ओआरएस, जिंक और क्लोरिन टेबलेट्स का वितरण।

स. त्वरित परीक्षण :

ऑन-साइट लैब द्वारा 15 मिनट में 'रेसिड्यूअल क्लोरीन' की जांच।

द. पर्यावरण उपचारः

सीवरेज सक्शन और ब्लीचिंग पाउडर) का भारी छिड़काव।

ई. सार्वजनिक चेतावनीः

लाउडस्पीकर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से 'नल का जल असुरक्षित है' की वैधानिक चेतावनी।

6. भविष्य हेतु रणनीतिक अनुशंसाएंः

संपूर्ण भारत के नगरों हेतु निम्नलिखित नीतिगत बदलाव अनिवार्य हैं-

1. 'जल-सीवर पृथक्करण अधिनियम': पेयजल और सीवर लाइन के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी का कानूनी प्रावधान।

2. जीआईएस (जीआईएस) मैपिंगः शहर की हर पाइपलाइन का डिजिटल मानचित्र और रिसाव का स्वचालित पता लगाने वाला तंत्र।

3. स्वतंत्र वैज्ञानिक आयोगः किसी भी संक्रामक मृत्यु की जांच के लिए स्थानीय प्रशासन से स्वतंत्र वैज्ञानिकों की एक स्थायी समिति।

4. जवाबदेही तय करनाः दोषी इंजीनियरों और अधिकारियों पर 'आपराधिक लापरवाही' के तहत मुकदमा।

7. भागीरथपुरा की घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि 'माइक्रोबायोलॉजिकल नरसंहार' है। यदि हम अब भी नहीं चेते, तो 'स्मार्ट सिटी' केवल एक कंक्रीट का जंगल बनकर रह जाएगी जहाँ जीवन की कोई गारंटी नहीं होगी। इस श्वेत-पत्र का उद्देश्य केवल आलोचना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और वैज्ञानिक भविष्य का निर्माण करना है। संदेशः भागीरथपुरा की त्रासदी ने सिद्ध किया है कि हमारे पास 'सुंदर शहर' के लिए बजट है, लेकिन 'सुरक्षित जीवन' के लिए 'इमरजेंसी रिस्पांस' शून्य है। यदि ऊपर लिखित 6-चरणीय प्रोटोकॉल को घटना के पहले 24 घंटों में लागू कर दिया जाता, तो ओम प्रकाश शर्मा और उन मासूम बच्चों की कुल 17 जान बचाई जा सकती थी।

कहीं मौसम में, कहीं सिस्टम में कोहरा

कटाक्ष

केदार शर्मा
लेखक व्यंग्यकार हैं।

मौसम विभाग चेतावनी जारी करता है– घना कोहरा छाया रहेगा। रहना भी चाहिए। हर चीज़ का अपना समय आता है। कोहरे के कारण दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कृत्रिम बरसात की तकनीक की तरह ही कोहरा हटाने की तकनीक भी विकसित होनी चाहिए।

कुछ लोगों को कोहरा फूटी आँख नहीं सुहाता। वे 24 कैरट पारदर्शिता की माँग करते हैं। उनका कहना है कि सड़क, रेल, समाज, नौकरशाही, राजनीति और व्यापार– हर क्षेत्र में सौ टंच पारदर्शिता होनी चाहिए। ठंड ही इतनी है कि उनके इस वक्तव्य के साथ-साथ, साँस के साथ भी कोहरा बाहर निकल रहा है।

विराधी निशाना साधते हैं– 'महोदय, आपकी कथनी और करनी में फ़र्क़ है। पहले अपनी साँस के साथ निकलने वाले कोहरे को तो रोक कर दिखाइए।'

इसलिए कोहरा हटाने की तकनीक लाने से पहले बहस ज़रूरी है। कोहरा पहले कहाँ से हटाया जाए और कहाँ से नहीं, सौ टंच पारदर्शिता से क्या-क्या नुकसान होंगे और क्या फायदे– इन मुद्दों पर बाकायदा बहस होनी चाहिए।

मौसम वाला कोहरा तो आएगा, छाएगा और चला जाएगा। उस कोहरे का क्या होगा, जो बिना चेतावनी आता है, छाता है, न छँटता है, न ही टलता है।

यह कोहरा मौसम का नहीं, सिस्टम पर छाया कोहरा है। इस कोहरे को हटाने की तकनीक विकसित होगी या नहीं– यह तो पता नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर पता है कि धूप की उष्मा पाते ही यही कोहरा तो हटने लगता है। समस्या यह है कि व्यवस्था पर छाए कोहरे को मिटाने आई जागरूकता की धूप को अक्सर टरका दिया जाता है। धूप पाँव नहीं जमा पाती और कोहरा बना रहता है। दुष्यंत कुमार ने अपनी किसी ग़ज़ल में कहा भी है

'मत कहो आकाश में कोहरा घना है,

यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।'

धूप रानी किसी कार्यवश दफ़्तर में दरख्वास्त लेकर गई। कोहरा सिंह ने दरख़्वास्त को रख लिया। जब पावती माँगी तो बोला– 'रख जाओ और घर जाओ। काम हो जाएगा बस।'

धूप रानी बोली– 'इस आवेदन को आवक रजिस्टर में चढ़ाइए और क्रमांक लिखकर पावती दीजिए।' दफ्तर में पेश की गई हर अर्ज़ी पर पावती देने का बाकायदा नियम है, कानून है और आपका उत्तरदायित्व है। हर पेशकार का अधिकार है।

कोहरा सिंह कुछ नहीं बोला। वह जानता है कि एक चुप सौ बलाओ की दवा है। हारकर वह सीधे बड़े साहब के पास गई। बड़े साहब ने आवेदन को कोहरा सिंह के नाम मार्क कर दिया। कोहरा सिंह ने गौर से देखा और कहा– 'ठीक है, रख जाओ और घर जाओ। सभी आवेदनों को वरीयता से बाद में रजिस्टर में चढ़ाएँगे।'

धूप रानी अड़ गई। अंगद के पाँव की तरह गड़ गई। बोली–

'पावती अभी लेनी है।' मन मारकर कोहरा सिंह ने आवेदन की फ़ोटो-कॉपी पर एक छोटी सी लकीर का निशान बना दिया। धूप रानी ने पूछा– 'भइए, यह किस चिड़िया के हस्ताक्षर है? न पद, न मोहर?'

कोहरा फिर चुप्पी पर छा गया। वह फिर बड़े साहब के पास गई। बड़े साहब आखिरकार कक्ष से बाहर आए और बोले– 'कोहरा सिंह, सभी दरख्वाखस्तों को जल्दी से रजिस्टर में चढ़ाओ।' कोहरा सिंह बड़े साहब को एक ओर ले जाकर कान में बोला– 'पावती देते ही समय-सीमा में काम करने का बंधन है, सर। दफ्तर में पहले ही बहुत काम पेंडिंग पड़ा है।'

बड़े साहब बोले– 'कोहरा सिंह, मैं तुम्हें अभी पावती के इस प्रभार से मुक्त करता हूँ। तुम्हें कार्य-निष्पादन शाखा में लगाया जाता है। तुम्हें धूप रानी के इस काम को तीन दिवस की सीमा में पूर्ण करने का आदेश दिया जाता है।'

आवक शाखा से कोहरा हट चुका था। नए प्रभारी से पावती पर क्रमांक, नाम, पदनाम और हस्ताक्षर-सहित मोहर पाकर धूप रानी मुस्कुरा रही थी। कोहरा सिंह अब निष्पादन शाखा से हटकर जावक शाखा में घुसने का जुगाड़ लगाने लगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

समझदार पति इस खेल के मैदान में नहीं कूदते

व्यंग्य

मुकेश नेमा
लेखक मप्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

पति के पास उपलब्ध सर और गर्दन का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल उसे उस वक्त हाँ में हिलाना है जब पत्नी साड़ी ख़रीदते वक्त किसी साड़ी के बारे में उसकी राय पूछे। किसी भी पति के लिये साड़ियाँ ख़रीदने का मौक़ा अपनी वफ़ादारी साबित करने का सबसे बेहतरीन मौक़ा होता है । कोई भी समझदार बंदा इसे गँवाता नही।वैसे तो आदमी पति होते ही समझदार हो जाता है। जो समझदार होने में देर करते हैं वो पति रह भी जायेंगे या नही, कब तक पति रह सकेंगे ये कहना मुहाल है।

और फिर समझदार होना बड़ा आसान भी है । आपको बस हाँ कहना होता है। पत्नी की हाँ में हाँ मिलना होती है।आपको इतना भर भाँपना है कि आपकी पत्नी किस साड़ी को पसंद कर चुकी है। पत्नी आपसे उस साड़ी बाबत आपकी राय जानना चाहती है जिसे व इसे जज होने का मौक़ा समझेगें तो गलती करेंगे। वो उस वक्त आपसे केवल और केवल हाँ की उम्मीद कर रही होती है।

साड़ियाँ आपको यह मौक़ा देती है कि पत्नी आपको कुछ वक्त के लिये ही सही पर खुशमिजाज, काबिल और होशियार मान ले। कई बार साड़ियाँ आपसे सच में समझदार होने की माँग करती हैं। फ़र्ज़ कीजिये आपकी पत्नी आधा दर्जन साड़ियाँ पसंद कर चुकी और अब चाहती है कि आप उनमे से एक दो पसंद कर दें । चूँकि आप अब तक बीबी की पसंद की गई साड़ियों के ढेर से दबे थे।सांस नहीं ली जा रही थी आपसे। ऐसे में एक या दो वाला ऑफ़र आपने जान डाल देता है। आप फ़ौरन उस ढेर में से कोई सी भी दो साड़ियाँ चुनते हैं और पत्नी को थमा देते हैं।

आप में यदि थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो आप उससे सारी साड़ियाँ ले लेने की ज़िद करते। पर अब आप गलती कर चुके। चुनी गई साड़ियों को लेकर घर पहुँचते पहुँचते आपकी पत्नी को छोड़ी गई साड़ियाँ ज़्यादा पसंद आने लगती है !। चूँकि वो साड़ियाँ ना ख़रीदी जाने की वजह आप है इसलिये डिनर भी आपका ही बिगड़ेगा ये बात भी तय हो जाती है।

अक्लमंद पति साड़ियों से घिरी बीबी के आसपास बना रहता है।अपने धीरज का दामन मज़बूती से थामे रखता है वो। बीबी उससे साड़ी देखने परखने की उम्मीद हांलाकि कभी करती नही। पर यदि करती है तो वह पूरी गंभीरता से यह ज़िम्मेदारी निभाता है।साड़ी का एक कोना पकड़कर उसे पूरे गौर से देखता है। टटोलता है और ख़ाक समझ में ना आने के बावजूद लग तो ठीक ही रही है जैसी अस्पष्ट सी राय देता है।साड़ी के बारे में साफ़ साफ़ हाँ या ना कहना ख़तरनाक होता है। ऐसे बड़े मामले निपटाने की कोशिश बाद में मुश्किल का सबब बन सकती है उसके लिए। वह जानता है कि ये मामला पत्नी खुद सुलटाये वही उसके लिये ठीक है।

वैसे पति जैसे जैसा पुराना होता जाता है उसे अकल आने लगती है। पुराना पति पत्नी की ख़रीदी गई साड़ियों पर चस्पाँ रेट के टैग को देखने की गलती नहीं करता। वह सामने मौजूद हर साडी को बढ़िया, बेहतरीन, माशाअल्लाह करार देता है।पत्नी के कलर च्वाईस पूछने पर लाल पीले नीले के फेर में ना पड़कर वह अपनी बीबी को हजार बार पहले भी कही जा चुकी बात एक बार फिर बताता है।वह उसे बताता है तुम पर हर कलर जँचता है। और ऐसी हर साडी जो उसे पसंद आ रही है ज़रूर ख़रीद ली जाना चाहिए।

साड़ी ख़रीदना वो खेल है जिसमें पति केवल दर्शक दीर्घा में ही रहता है। समझदार पति इस खेल के मैदान में नहीं कूदते और दूर से अपनी सीट पर बैठे बैठे केवल तालियाँ बजाते है। समझदार हो चुका पति जानता है कि साड़ियाँ ख़रीदना एक कला है जिसमें उसकी पत्नी पारंगत है। ये वो कौशल है जिसमें उसकी पत्नी का हाथ हमेशा से साफ़ है। ये वो लडाई है जिसे उसकी पत्नी ही जीत सकती है। ऐसे में वो साड़ी ख़रीदने जैसे बेहद ख़ास काम से दूरी बनाये रखता है और सुखी बना रहता है।

जब पत्नी साड़ियाँ ख़रीद रही हो।साड़ियों की दुकान पर युग बीत चुके हों। ऐसे वक्त पर घड़ी देखना, मुँह बनाना,सर खुजलाना जैसी हरकतें आपका नुक़सान कर सकती हैं।यदि आप नही चाहते कि आपकी पत्नी आपको बच्चों के सामने, सिर्री, अकडू और बोर करार दे दे तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। पत्नी के साड़ी ख़रीदो कार्यक्रम के दौरान जो पति अनमना होकर दिखाता है। उबासी लेता है या पाँव पटकता है ,उसे गधा मानने मे मुझे क़तई दिक्क़त है नहीं। ऐसे पति अपनी पत्नी से उसी बर्ताव के लायक़ है जैसे एक नाराज़ कुम्हार अपने गधे के साथ करता है।

आप किस क़िस्म के पति है मैं नहीं जानता पर इतना भर कहना है मेरा कि यदि आपने शादीशुदा होने के बावजूद साड़ी ख़रीदने जैसे नाज़ुक वक्त में अपनी गर्दन और उसके ऊपर मौजूद सर को क़ायदे से हिलाना अब तक नहीं सीखा है तो बिना देर किये अब सीख लें। इसलिये सीख लें ,क्योंकि आपकी गर्दन साड़ियों से ज़्यादा क़ीमती है।

व्यंग्य

शांतिलाल जैन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

आर्यावर्त में बरस छब्बीस के सामने चुनौतियाँ

मैंने रिहा करवाए हत्याओं के, बलात्कार के सज़ायाफ्ता मुजरिम। जिन्हें मुआफ़ नहीं करा सका उनको परोल पर बाहर लाकर दिखाया है। संख्या में वे दस-बीस हैं मगर हैं रसूखवाले। धार्मिक और संस्कारी इस कदर कि परोल पर भी आते हैं तो सत्संग-कथा करना नहीं भूलते। वे उन लाखों कैदियों से अलग हैं जिनके पास न वकील की फीस है न मुचलका भरने का पैसा। वे विचाराधीन हैं मगर उनको न्याय दिलाने वाला सिस्टम विचार शून्य। उनकी चुनौती तो चुनौती है भी नहीं। असल खेल तो रसूखदारों को आज़ाद करने करवाने का है। इससे बड़ी चुनौती रसूखदारों को कानून की पहली सीढ़ी से ही बचा ले जाने की है। कामयाब रहा हूँ मैं। तुम कर सकोगे?

हैलो, 1 जनवरी, 2026,

मैं 2025 बोल रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं, मगर बताता चलूँ कि तुम साल भले नए हो चुनौतियाँ तुम्हारे सामने वे ही पुरानी हैं। बस उसका स्केल बढ़ाते जाना है। बीते पूरे बरस अनैतिकताओं की खाईयों में आर्यावर्त के गिरते रहने का मैंने सिलसिला थमने नहीं दिया, बल्कि उसे बढ़ाया ही है। 2024 के बरक्स मैंने झूठ, कपट, छ्ल, धोखे के नए कीर्तिमान गढ़े हैं, अब बैटन तुम्हारे हाथ है, निचाईयों के नए कीर्तिमान गढ़ने की चुनौती है तुम्हारे सामने।

मैंने रिहा करवाए हत्याओं के, बलात्कार के सज़ायाफ्ता मुजरिम। जिन्हें मुआफ़ नहीं करा सका उनको परोल पर बाहर लाकर दिखाया है। संख्या में वे दस-बीस हैं मगर हैं रसूखवाले। धार्मिक और संस्कारी इस कदर कि परोल पर भी आते हैं तो सत्संग-कथा करना नहीं भूलते। वे उन लाखों कैदियों से अलग हैं जिनके पास न वकील की फीस है न मुचलका भरने का पैसा। वे विचाराधीन हैं मगर उनको न्याय दिलाने वाला सिस्टम विचार शून्य। उनकी चुनौती तो चुनौती है भी नहीं। असल खेल तो रसूखदारों को आज़ाद करने करवाने का है। इससे बड़ी चुनौती रसूखदारों को कानून की पहली सीढ़ी से ही बचा ले जाने की है। कामयाब रहा हूँ मैं। तुम कर सकोगे?

अपने समयकाल में पूरी शिद्दत से मैंने रिश्वतें कम नहीं होने दीं। लेने वालों में जिनको बचाना था उनको बचाए भी रखा। जिन्हें यहाँ महफ़ूज़ नहीं रख सका उन्हें सात समंदर पार बसा दिया है। सीढ़ीयाँ मुहैया करवाईं कि कुछ लोग अमीरी के टॉप इतने या टॉप उतने में पहुँच सकें, गरीबी की खाईयाँ गहरी-चौड़ी करवाईं कि जो किसी तरह मुहाने पर खड़े हैं वे गिर सकें, जो गिरे हैं गिरे रहें। चुनौती है तुम्हारे सामने हमारे समय के रसूख़दार कितना भी भ्रष्ट आचरण करें मगर रहें क़ानून की गिरफ्त से दूर-दूर। इसे तुम हलके में मत लेना डियर, बचाने का एक ही पैमाना रखना - 'वो उनके साथ है, वो उनके साथ नहीं है।'

ओ छब्बीस, सुनिश्चित करना कि नफरतों के परनालों का उफान कायम रहे। रंग बेशर्म हो न हो रंगदार बेशर्म हों, रंगदारी बेशर्म हो। जातियों, धर्मों, भाषाओं के पचड़े में इंसान भूल जाए कि वो इंसान है और एक इंसान को बरत रहा है। इंसान का खून काऊ-यूरिन से सस्ता हो। वो शंका-आशंका में भीड़ बनाकर किसी को भी मार डाले, वो होस्टल में नारे लगाने, नहीं लगाने की हिंसा का शिकारहो। वो किताबों से ज्यादा कपड़ों पर आन्दोलन करे। जिससे प्यार करे उसके टुकड़े टुकड़े जंगलों में फैला दे। जिसे नहीं कर पाए उस पर एसिड अटैक कर डाले। महिलाएँ बचनी नहीं चाहिए। अबला किसी भी धरम की हो, जाति की हो, उम्र की होङ्कउस पर अत्याचार कम मत होने देना ओ अनुवर्ती बरस।

नफरत के पुआल में लगी चिंगारी को मैंने बहुत कुछ हवा तो दी मगर आर्यावर्त अभी पूरी तरह जलना बाकी है। तुम्हें करना है। शांति, करूणा, अहिंसा, सहिष्णुता के पाठ पढ़ानेवाले धर्म के नाम पर अशांति, घृणा, हिंसा का बोलबाला हो। देश आहत आस्थाओं का देश बना रहे। विश्वास अंधविश्वास में बदलता रहे। तारीख़ इक्कीसवीं सदी की हो, तवारीख़ सोलहवीं सदी की। तर्क और विज्ञान कुरीतियों के समक्ष नाक रगड़ते आएँ। शिक्षा मिले तो मदरसों, मिशनरियों, आश्रमों में मिले। जहां भी मिले मध्ययुगीन मिले। पढ़े-लिखे लोग भी गंडे-ताबीज़ में भरोसा रखें। सोच दकियानूसी बने और जनमानस तांत्रिकों के फेर में अकर्मण्य। बारह मास बाद एक नफरतों से जलता मुल्क देते हुए जाना डियर।

मैंने अपने पूरे साल में कीमतों के आकाशगामी होने को बनाए रखा। अब तुम्हारे सामने दोहरी चुनौती है - जरूरी जिंसों के दाम अव्वल तो कम न हों बल्कि बढ़ें। रहें तो मेरे लेवल से उपर ही रहें। निज़ाम जैसे जैसे नियंत्रण में होने के बयान दे वैसे वैसे दाम बढ़ते रहें। सिक्का लुढ़कने की नई निचाईयों को छुए। जो रोज़गार में हैं वे छटनियों के शिकार हों, जो रोजगार में नहीं हैं वे पंखों से रस्सी डालकर झूलते रहें। नए साल में आरक्षण का नया उत्साह हो, प्रतिशत निनानवे हो मगर नौकरियाँ हो ही नहीं। रिजर्वेशन कन्फर्म, ट्रेन केंसिल। एक रात में हज़ारों की छटनीं हो जाए और लेबर मिनिस्टर की उफ़ भी सुनाई न दे। छलावे के नए कीर्तिमान रचने की चुनौती है तुम्हारे सामने डियर ट्वेंटी सिक्स। मरें तो अकेले बेरोजगार क्यों मरें, किसान भी क्यों न मरे, करियर बनाने के दबाव में युवा भी मरे, क़र्ज़ वसूली से परेशान भी मरे, ले-ऑफ़ का शिकार भी मरे? बरस छब्बीस तुम्हें चैलेंज है - किस पेशे से कितनी हाराकीरी करवा पाते हो तुम।

और हाँ, सरकार के भरोसे मत रहना। सरकारें चुनौतियाँ उनको मानती हैं जो उनकी सत्ता को होती है। वे संविधान के प्रावधानों में गली ढूंढकर संविधान की आत्मा मारते रहें तभी तुम्हारे आनेवाले बावन सप्ताह सफल मानियो। मैं सफल रहा कि जो इंसान के मूल अधिकारों के लिए लड़ते रहे वे कारावास से बाहर न आ सके, तुम और अधिक सड़ा सको उन्हें। एक ऐसा समाज गढ़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना है तुम्हें जहाँ बुद्धिजीवियों को देश का दुश्मन माना जाने लगे। जो पर्यावरण बचाने की लड़ाई लड़ें उन्हें कारावास हो। जल, जंगल, जमीन बचे नहीं, बिके। हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जाए। निनानवे मीटर तक ऊँचा पहाड़ पहाड़ न माना जाए। पानी जमीन के नीचे का नहीं आँखों का भी निरंतर सूखता रहे।

न्यूजट्वंटी-फोर-बाय-सेवेन मिले मगर उसमें समाचार न हो। मीडिया आगे बढ़े ऐसे जैसे केंचुआ बढ़ता है। हड्डियों से परहेज़ रखना दोस्त दरबार में रेंगने में बाधा उत्पन्न होती है। महानगर की सड़कों पर पानी भर जाए तो मिडिया आसमान सर पर उठाले मगर दूर देश में लाखों लोग हफ़्तों बाढ़ में घिरे रहें, बेघर हो जाएँ और तूती भी आवाज़ न करे। इंडेक्स शेयर बाज़ार का बढ़े डेमोक्रेसी का गिरे, प्रेस फ्रीडम का गिरे, भुखमरी का गिरे, करप्शन का गिरे।

न्याय अदालतों से नहीं जेसीबी से मिले। राज़ पुलिस का हो, न्याय जंगल का, मुकदमें कंगारू कोर्ट में निपटाएँ जाएँ। मैं तो नहीं कर सका मगर तुम कर सकते हो- इसी बरस आला अदालत को सरकार-ए-हिन्द की बांदी बना सको तो। चैलेंज कठिन है मगर तुम कर सकते हो।

ओ अनुवर्ती वर्ष, तुम तैयार रहना आतंकी हमलों से लेकर अचानक बाढ़ तक सहने के लिए, हिमस्खलन से लेकर पुल तक के गिरने के लिए, विमान दुर्घटना से लेकर भगदड़ तक में मरने के लिए, भूस्खलन से लेकर फैक्ट्री विस्फोट तक में मरने के लिए। तुम तैयार रहना युद्ध के लिए, वनों की कटाई, पहाड़ों की खुदाई के लिए, अत्यधिक भ्रष्टाचार के लिए, डिजिटल अरेस्ट के लिए, साइबर धोखाधड़ी के लिए, हवाई अड्डे पर अटके रहने के लिए, रेल के निरस्त हो जाने के लिए, नए श्रम क़ानून से पिटने के लिए, वोटर लिस्ट से कटा नाम जुड़वाने की लाइन में लगने के लिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ - ये देश तुम्हारी बढ़ती ज्यादतियों पर उफ़्फ़ भी नहीं करेगा।

बहरहाल, समय कम है चुनौतियाँ अधिक, महज़ तीन सौ पैंसठ दिन हैं तुम्हारे पास। अपनी फितरतों, हरकतों, कारनामों, कमीनगियों, गिरावटों के मेरे कीर्तिमानों से तुम कितना और नीचे गिर सकते हो डियर ट्वेंटी सिक्स इसका आकलन हम 31 दिसंबर, 2026 की शाम करेंगे। भरोसा है मुझे, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अलविदा और मुबारकें।

संघ शताब्दी वर्ष

डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी

लेखक स्तंभकार हैं।

बैतूल की जेल में लिखा गया था आरएसएस का संविधान

गांधी जी की दुखद हत्या के पश्चात् नेहरू सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुरुजी सहित बीस हजार अग्रणी स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस समय के प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्र 'केसरी' के संपादक केतकर जी सरकार व संघ के मध्य संवाद करा रहे थे। केतकर जी 12 व 16 जनवरी 1649 को गुरुजी से सिवनी कारागार में मिले थे। उन्होंने गुरुजी से संघ के सत्याग्रह को समाप्त करने का आग्रह किया। गुरुजी ने परिस्थितियों का आकलन किया व आंदोलन स्थगित कर दिया। 22 जनवरी को संघ के सत्याग्रह प्रभारी महावीर जी ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। तब जाकर कहीं सरकार ने राहत की साँस ली थी।

सर्वविदित है कि गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर बैतूल के कारागार के बैरक क्र. 1 में रह चुके हैं। वे यहाँ 1 जनवरी 1949 से 6 जून 1949 तक बंदी रहे थे। बैतूल कारागार के जिस बैरक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी को बंदी बनाकर रखा गया था वह कक्ष आज भी एक लघु स्मारक के रूप में रिक्त रहता है। इस कक्ष में गुरुजी का एक चित्र लगा हुआ है व उनके कारागार प्रवास के संदर्भ में कक्ष की दीवार पर संक्षिप्त लेखन भी है। बैतूल जेल के इस लघु स्मारक को अब एक दिव्य स्मारक में परिवर्तित करने की चाह देश भर के स्वयंसेवकों में है। वर्ष 2017 में सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत ने भी जेल के इस कक्ष में जाकर गुरुजी को श्रद्धासुमन अर्पित किए थे।

गांधी जी की दुखद हत्या के पश्चात् नेहरू सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुरुजी सहित बीस हजार अग्रणी स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस समय के प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्र 'केसरी' के संपादक केतकर जी सरकार व संघ के मध्य संवाद करा रहे थे। केतकर जी 12 व 16 जनवरी 1649 को गुरुजी से सिवनी कारागार में मिले थे। उन्होंने गुरुजी से संघ के सत्याग्रह को समाप्त करने का आग्रह किया। गुरुजी ने परिस्थितियों का आकलन किया व आंदोलन स्थगित कर दिया। 22 जनवरी को संघ के सत्याग्रह प्रभारी महावीर जी ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। तब जाकर कहीं सरकार ने राहत की साँस ली थी।

यह भी एक स्मरणीय तथ्य है कि संघ पर 1948 में लगे प्रतिबंध हटाने की भूमिका भी बैतूल जेल के बैरक क्र. 1 में ही लिखी गई थी। देश के प्रमुख समाचार पत्र 'द ट्रिब्यून' ने 22 जन. 1949 को संघ प्रतिबंध को अनैतिक बताते हुए लिखा - 'अब नेहरू सरकार को संघ से प्रतिबंध हटा लेना चाहिए'। संघ के इस आंदोलन के प्रति देश की जनता में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए नेहरू सरकार घबरा गई थी। सरकार ने तत्काल ही पाँसा फेंका और प. मौलिचन्द्र शर्मा को संघ से चर्चा करने हेतु आगे बढ़ाया।

इस समय तक गुरुजी को सिवनी कारागार से बैतूल कारागार में स्थानांतरित किया जा चुका था। 10 जुलाई को मौलिचन्द्र शर्मा गुरुजी से भेंट करने बैतूल जेल आए थे। बैतूल जेल से ही श्री गुरुजी एवं मौलिचन्द्र शर्मा की चर्चा के आधार पर नेहरू जी ने 12 जुलाई को संघ से प्रतिबंध हटाया था व 13 जुलाई को प्रातः समय में गुरुजी को बैतूल जेल से मुक्त कर दिया गया था।

बैतूल जेल से निकलने के तत्काल बाद ही श्री गुरुजी जीटी एक्सप्रेस से नागपुर चले गए थे। श्री गुरुजी के बैतूल से प्रस्थान के समय का एक किस्सा संघ क्षेत्रों में बहुधा ही कहा सुना जाता है। कहा जाता है कि, श्री गुरुजी ने बैतूल स्टेशन पर छोड़ने आए स्वयंसेवकों से कहा था - 'जिस दिन बैतूल में संघ का कार्य सुदृढ़ और संपुष्ट हो जाएगा उस दिन समूचे देश में संघ विचार सुदृढ़ हो जाएगा'।

बैतूल जेल में गुरुजी के बंदी रहने के समय को दुखद किंतु ऐतिहासिक काल कहा जाता है। गुरुजी ने इस विकट, दुधूर्ष अग्निपरीक्षा के समय में अद्भुत धैर्य का परिचय देते हुए बैतूल जेल से अनेकों पत्रों व संवादों के माध्यम से देश भर के स्वयंसेवकों के मनोबल को बनाए रखा था। बैतूल देश की धड़कनों के केंद्र में आ गया था। बैतूल जेल में रहते हुए ही गुरुजी ने नेहरू सरकार पर इतना दबाव बना लिया था कि नेहरू सरकार को न चाहते हुए भी गुरुजी को जेल से मुक्त करना पड़ा था।

गुरुजी को बैतूल कारागार में नाना प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। उन्हें भोजन, पहनने को कपड़े व कंबल आदि अत्यंत निम्नस्तरीय प्रकार के दिए जाते थे। कष्ट, प्रताड़ना, व निम्न स्तरीय भोजन, वस्त्र से उत्पन्न कष्ट से श्रीगुरुजी को कोई अन्तर नहीं पड़ता था। वे तो निस्पृह योगी थे। बिना भगवा पहने ही एक महान सन्यासी थे। उन्होंने बैतूल जेल में मिले उस सम्पूर्ण गरल को नीलकंठ बन अपने कंठ में स्थिर कर दिया था। बैतूल जेल उनके लिए एक साधना केंद्र हो गई थी।

बैतूल कारागार में गुरूजी ने संघ का संविधान तैयार करने के कार्य को प्रारंभ व पूर्ण किया था व अपने हस्ताक्षर के साथ इसे जारी किया था। गुरु गोलवलकर जी का बैतूल जेल प्रवास संघ के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, और, बैतूल की यह जेल संघ के संविधान की जन्मस्थली। बैतूल कारागार में रहते हुए गुरुजी ने संघ की राजनाति में शुचिता, पवित्रता व समाज योगदान के संदर्भ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ बहुत व्यापक पत्राचार किया। इन पत्रों को बाद में 'जस्टिस ऑन ट्रायल' नामक पुस्तक में प्रकाशित भी किया गया था।

आज बैतूल जिले की यह ऐतिहासिक जेल निजी क्षेत्र को विक्रय कर तोड़े जाने के कगार पर है आवश्यकता इस बात की है कि जेल परिसर में निर्मित इस 'गुरुजी कक्ष' को या 'संघ संविधान जन्म कक्ष' को सुरक्षित रखकर एक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाए।

पुस्तक समीक्षा

दीपक गिरकर

समीक्षक

सकारात्मक सोच का संदेश देती कहानियाँ

'स्नेहवीरा' प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन दिखाती संवेदनशील कहानी है। गौरी न केवल सैनिक की पत्नी, बल्कि आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित समाजसेविका के रूप में उभरती है। देवाशीष का चरित्र आदर्श सैनिक का प्रतीक है। अमरनाथ आपदा पृष्ठभूमि कहानी को यथार्थपरक बनाती है। 'हरित चेतना' कहानी में मुंबई स्टेशन पर भिखारी को देखकर युवाओं में संवेदना जागती है और वे समाज सेवा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित होकर पुराने जूतों को रीसायकल कर गरीबों के लिए उपयोगी बनाते हैं। 'ठुनकती कोपलें' कहानी में पिताङ्क्षपुत्र के रिश्ते, त्याग और संवाद का मार्मिक चित्रण है। कहानी भूल और आत्मग्लानि के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों और संवेदनशीलता को उजागर करती है। 'बैम्बू प्रोजेक्ट' कहानी में परंपरागत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का द्वंद्व है। कहानी बाँस के आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय महत्व को सरल ढंग से प्रस्तुत करती है।

'रंग से रश्मियों तक' डॉ. वसुधा गाडगिल का पहला कहानी संग्रह है। इनकी रचनाएँ निरंतर देश की लगभग सभी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इन कहानियों के माध्यम से लेखिका ने आज के जीवन और समाज के विविध पक्षों को संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। लेखिका ने समाज में घटित घटनाओं, अनुभवों और परिवर्तनों का गहन अवलोकन और मंथन किया है, जो इन कहानियों में यथार्थ और मानवीय संवेदना के संतुलित और मार्मिक रूप में व्यक्त होता है। यह कथा-संग्रह न केवल सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण प्रस्तुत करता है, बल्कि प्रत्येक कहानी में निहित सकारात्मक दृष्टिकोण पाठकों को आशा, विश्वास और मानवीय मूल्यों से जोड़ने का कार्य भी करता है। इस संग्रह की कहानियाँ जीवन के विविध अनुभवों को आत्मीयता से प्रस्तुत करते हुए पाठक को चिंतन के साथ-साथ संवेदना की यात्रा पर ले जाती हैं।

'स्नेहवीरा' प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन दिखाती संवेदनशील कहानी है। गौरी न केवल सैनिक की पत्नी, बल्कि आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित समाजसेविका के रूप में उभरती है। देवाशीष का चरित्र आदर्श सैनिक का प्रतीक है। अमरनाथ आपदा पृष्ठभूमि कहानी को यथार्थपरक बनाती है। 'हरित चेतना' कहानी में मुंबई स्टेशन पर भिखारी को देखकर युवाओं में संवेदना जागती है और वे समाज सेवा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित होकर पुराने जूतों को रीसायकल कर गरीबों के लिए उपयोगी बनाते हैं। 'ठुनकती कोपलें' कहानी में पिता-पुत्र के रिश्ते, त्याग और संवाद का मार्मिक चित्रण है। कहानी भूल और आत्मग्लानि के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों और संवेदनशीलता को उजागर करती है। 'बैम्बू प्रोजेक्ट' कहानी में परंपरागत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का द्वंद्व है। कहानी बाँस के आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय महत्व को सरल ढंग से प्रस्तुत करती है। 'सिंधु सम्राज्ञी' सामाजिक बाधाओं, भय और सीमित साधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प और संघर्ष की प्रेरक गाथा है। यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण है। 'रंग से रश्मियों तक' कहानी में रंगभेद और आत्मसम्मान का संघर्ष है। एलीना का टेनिस में विजय प्राप्त करना मानसिक और सामाजिक बंधनों पर जीत का प्रतीक है। पिता का समर्थन और आत्मगौरव कहानी की ताकत है। 'लौट आई माँ' कहानी मातृत्व और आधुनिक जीवन के द्वंद्व को मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। सारा की बीमारी पर बेला का निर्णय माँ के प्रेम और स्नेह की शक्ति दिखाता है। 'एक डगर' कहानी में आधुनिक सोच, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश है। नव्या का चरित्र स्पष्ट और प्रेरक है। सही मार्ग अपनाने से सफलता और संबंधों में स्थायित्व मिलता है। 'तब पलाश दहक उठा' कहानी में गहरे दुःख और अकेलेपन के बीच आशा और प्रेम का संचार है। सात्विका के प्रेम और संवेदनशीलता से साकेत के जीवन में नई चेतना का आगमन होता है। 'बारबेक्यू' टूटते दांपत्य रिश्तों को संवेदनशील ढंग से जोड़ने वाली कहानी है। साझा अनुभव और संवाद के माध्यम से संबंधों में गर्माहट लौटती है। 'बंदी मन, खुलती बेड़ियाँ' डिजिटल माध्यम और मानसिक गुलामी पर प्रभावी कहानी है। परेश का सकारात्मक मार्गदर्शन बुलबुल को अपराध की मानसिक बेड़ियों से

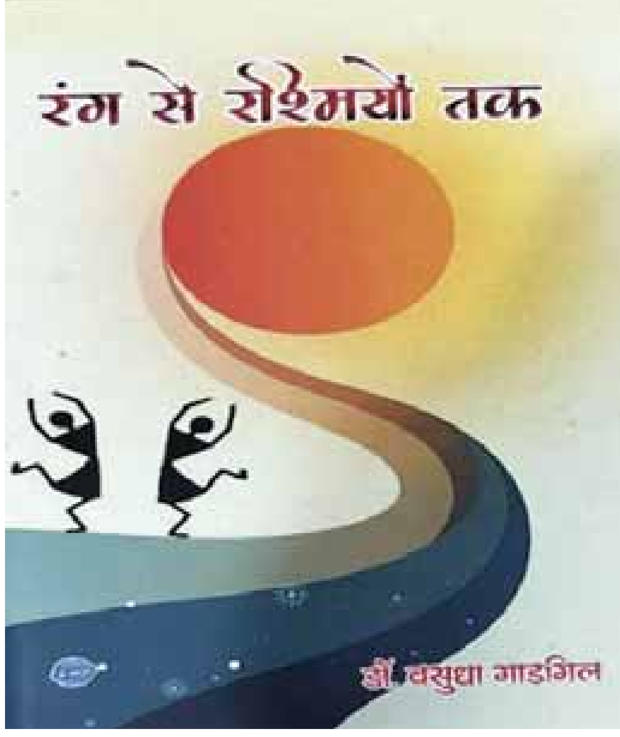

बाहर निकालता है। 'खिलखिलाती दीवारें' कहानी वृद्धावस्था में अकेलेपन और अपनत्व की आवश्यकता को रेखांकित कराती है। कहानी में रक्त संबंध से परे भावनात्मक जुड़ाव और परिवार में खुशी का संदेश है। 'मिट्टी की सौंधी सुगंध-सी' कहानी में विधवा नारी का संघर्ष, पारिवारिक षड्यंत्र और माँ-बेटे के रिश्ते की पुर्नस्थापना है। डॉक्टर जयंत की संवेदनशील मदद से रोहन का व्यवहार सुधरता है। 'टूटे सपनों की आवाज़' कहानी में नशे की बुराई और उसके भयावह परिणाम को दर्शाया गया है। कहानी में मातृत्व, ग्लानि और सामाजिक चेतना का मार्मिक चित्रण है। बच्चों की दौड़ के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। 'दूर ज़मीन पर खुशियाँ' संघर्ष, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनाओं की कहानी है। दूरदेश में कठिनाइयों के बावजूद कर्मठता और संवेदनशीलता से जीवन में खुशियाँ और संतोष प्राप्त होते हैं।

इन कहानियों में ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश की यथार्थवादी और मार्मिक झलक प्रस्तुत की गई है। लगभग प्रत्येक कहानी में डॉ. वसुधा गाडगिल समाज की किसी न किसी समस्या को पूरी पारदर्शिता के साथ अभिव्यक्त करती हैं। ये कहानियाँ कथाकार के जीवन अनुभवों और परिवेश से उपजी हैं, जिनमें सामाजिक विडम्बनाएँ, मानवीय कुंठा-हताशा, रिश्तों की जटिलता, नस्लवाद, प्रौद्योगिकी के दुष्प्रभाव तथा नारी संघर्ष की अभिव्यक्ति है। ये रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत कहानियाँ हैं। वसुधा जी की कहानियाँ पात्रों और परिवेश के माध्यम से आन्तरिक संवेदना को झकझोरती हैं। संवेदनशील कथाकार डॉ. वसुधा गाडगिल की कहानियाँ मानवीय संबंधों को हर कोण से देखती हैं। सभी कहानियों के कथ्य प्रभावशाली हैं। सभी कहानियाँ घटना प्रधान हैं। इस कहानी संग्रह की हर एक कहानी नारी के मन और उसकी भावनाओं के हर एक पहलु को उजागर करती है। वसुधा जी की कहानियाँ समाज के ज्वलंत मुद्दों से मुठभेड़ करती है और उस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करती है। सकारात्मक सोच का संदेश देना इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है। कथाकार ने समकालीन सच्चाइयों तथा परिवार में स्त्रियों की हालत को निष्पक्षता से प्रस्तुत किया है। ये कहानियाँ कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से पाठकीय चेतना पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। इनकी कहानियों में विविधता है। लेखिका कहानियों में नये नये विषयों को उठाती हैं। ये कहानियों में भाषा और शिल्प में भी नये नये प्रयोग करती हैं। पात्रों के अनुरूप छोटे छोटे संवाद हैं जो उचित लगते हैं।

पुस्तक : रंग से रश्मियों तक (कहानी संग्रह)
लेखिका : डॉ. वसुधा गाडगिल
प्रकाशक : सर्व भाषा ट्रस्ट, नई दिल्ली
मूल्य : 249/- रूपए

स्कूल और आंगनवाड़ी में रहा अवकाश, दो दिन में गिरा 3.5 डिग्री पारा

जिले में सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, तापमान 7.5 डिग्री दर्ज

बैतूल। जिले में लगातार ठंड बढ़ते जा रही है। हालात यह है कि बीते चार दिनों में 3.5 डिग्री पारा नीचे लुढक गया है। सोमवार रात जहां तापमान 9.2 डिग्री था, वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 2.0 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पारा गिरने के कारण शीतलहर का असर भी तेज हो गया है। लोग दिन में भी अलाव जलाकर ठंड से बचते देखे गए। बता दे कि नई साल की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज भी रोज बदल रहा है। नए साल की शुरुआत में ठंड से कुछ राहत मिली थी। 2 जनवरी को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और 3 जनवरी को 12.5 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि जनवरी के पहले सप्ताह के अंत में ठंड ने फिर से वापसी कर ली है और तापमान लगातार नीचे आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 6 जनवरी को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के आंकडों के मुताबिक, 2 जनवरी को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 25.5 डिग्री सेल्सियस था। वहीं, 6 जनवरी को यह घटकर क्रमशः 7.5 डिग्री और 22 डिग्री सेल्सियस रह गया। इस तरह पिछले चार दिनों में रात के तापमान में 3.5 डिग्री और दिन के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई है। मंगलवार को आसमान साफ रहने से धूप खिली, जिससे थोडी राहत मिली, लेकिन ठंडी हवाएं चलती रहीं। वहीं विजिबिलिटी 10 से 20 किमी थी।

नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक रही छुट्टी ...

जिले में लगातार पड़ रही शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए मंगलवार एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि जिन विद्यालयों में परीक्षाएं या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां पहले से निर्धारित हैं, वे पूर्ववत संचालित रही और उन पर अवकाश का कोई असर नहीं पड़ा। इसी के साथ, जिले की आंगनवाड़ियों में भी शीतलहर की स्थिति को देखते हुए अवकाश रहा। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाव के पर्याप्त उपाय करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

दो दिन में गिरा 3.5 डिग्री तापमान ...

शीत लहर चलने से जिले में ठिठुरन बढ़ गई। सोमवार को न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। इधर घना कोहरा छाने से दृश्यता कम रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले दस दिनों से बैतूल में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। 26 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री था, जो 27 दिसंबर को 8.7 डिग्री और 28 दिसंबर को 8.5 डिग्री तक गिर गया था। हालात यह है कि सोमवार को सुबह के समय शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। ठंड बढने के कारण जगह-जगह लोगों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास किया।

खेतों के किनारे धुआं करें और हल्की सिंचाई करें

विशेषज्ञों के अनुसार ठंड गेहूं के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन पाला पडने से चना, मसूर और मटर जैसी फसलों में इल्ली सहित अन्य रोगों की संभावना बनी रहेगी। इन्हें समय पर नहीं रोका गया, तो उत्पादन पर असर पड़ेगा। जैसे ही कीट या रोग के लक्षण दिखें, किसान तुरंत उपचार करें। मौसम रबी फसलों के लिए अनुकूल है, लेकिन सतर्कता और समय पर प्रबंधन जरूरी है। तभी किसान इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को पाले से फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करने को कहा है। रबी की फसलें, खासकर चना, मटर, आलू, धनिया और तिलहनी फसलें पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। विभाग ने किसानों को रात में खेतों के किनारों पर कचरा जलाकर धुआं करने और हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। सुबह फसलों को रस्सी से हल्का हिलाने को कहा गया है, ताकि पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें गिर जाएं। इसके अलावा सल्फर डस्ट, ग्लूकोज या पोटेशियम सल्फेट का छि?काव करने की भी सलाह दी गई है।

पिछले एक सप्ताह का जिले का तापमान

तिथि	अधि.	न्यून.
29 दिसंबर	25.5	8.8
30 दिसंबर	26.2	9.0
31 दिसंबर	26.5	9.5
1 जनवरी	26.7	11.5
2 जनवरी	26.0	11.7
3 जनवरी	26.2	12.5
4 जनवरी	26.0	11.5
5 जनवरी	25.5	9.2
6 जनवरी	22.0	7.5

सीएमएचओ ने खेड़ी सांवलीगढ़ और डहरगांव के टीकाकरण सत्रों का किया निरीक्षण

बैतूल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाडे ने 6 जनवरी को ग्राम डहरगांव एवं खेड़ी सांवलीगढ में टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया। टीकाकरण सत्र पर सीएचओ, एएनएम उपस्थित पाई गईं। सीएमएचओ द्वारा ग्राम में टीकाकरण सत्र के निरीक्षण के दौरान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में आई महिलाओं से चर्चा कर ग्राम में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित

हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के लाभ एवं जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य एवं पोषण पर समझाइश दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीकाकृत बच्चों एवं टीकाकरण पंजी चेक की। ग्राम खेड़ी सांवलीगढ के गांधी वार्ड आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थित हितग्राहियों द्वारा उनके बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की नियमित रूप से जांच करने एवं बच्चों को समय पर टीकाकरण किए जाने पर कार्यरत सीएचओ एवं एएनएम की प्रशंसा की। सीएमएचओ ने सीएचओ एवं एएनएम को जनसमुदाय से जुडक़र बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। सीएमएचओ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेडी सांवलीगढ़ का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने समस्त स्टाफ को समय पर अस्पताल में उपस्थित रहकर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेहरा को खेडी सांवलीगढ़ में इसी माह से प्रसव केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

हिन्दू सम्मेलन से पहले शहर में धर्मजागरण की लहर, जगह-जगह हो रही भारत माता की आरती

बैतूल। सकल सनातन हिन्दू समाज बैतूल द्वारा 11 जनवरी रविवार को जेएच कॉलेज के अटल सभागृह में आयोजित होने वाले हिन्दू सम्मेलन को लेकर शहर में लगातार धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जा रही है। गायत्री बस्ती, गंज एवं सिविल लाइन क्षेत्र में चौक-चौराहों और मोहल्लों में भारत माता की आरती, कलश यात्राएं, प्रभात फेरियां और वाहन रैलियों

के माध्यम से लोगों को सम्मेलन के लिए एकजुट किया जा रहा है। हिन्दू सम्मेलन के मीडिया प्रभारी राजेश मदान ने बताया कि क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में एकत्र होकर भारत माता की भव्य आरतियां कर रहे हैं। सुबह प्रभात फेरियां और वाहन रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही घर-घर पीले चावल और आमंत्रण पत्र पहुंचाकर सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार रात्रि 8 बजे गंज क्षेत्र के माता मंदिर के पास स्थित भगतसिंह चौक पर भारत माता की भव्य आरती का आयोजन किया गया। ढोल-ढमाकों के साथ जय श्रीराम और भारत माता की जय के उद्घोष के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक आरती में सहभागिता की।

बैतूल में भी काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया विरोध

बैतूल। मध्यप्रदेश अजाक्स एवं समस्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समाज के संगठनों के आव्हान पर मंगलवार को संपूर्ण मध्यप्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराया। यह विरोध अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा (आईएएस) के समर्थन में किया गया। ज्ञात हो कि विगत दिनों संतोष वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा था कि जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि जातियां खत्म कर दो, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वे आईएएस हैं, तो क्या उनके परिवार से रोटी-बेटी का संबंध वर्ग विशेष बना लेगा। जब तक समाज में रोटी-बेटी के संबंध नहीं बनते, भेदभाव समाप्त नहीं होता और सामाजिक समरसता स्थापित नहीं होती, तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए। उनके इस बयान को गलत रूप में प्रस्तुत कर एक वर्ग विशेष द्वारा विरोध किया गया था।

बैतूल के 80 वर्षीय रिटायर्ड बैंक अधिकारी से ठगी

दिल्ली पुलिस बनकर डिजिटल अरेस्ट रखा, 23.50 लाख ऐंठे, केस दर्ज

बैतूल। जिले में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। गंज थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से 23 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई है। जिसकी शिकायत पीड़ित ने की है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 318(4), 308 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बसंत कुमार मैदमवार निवासी विनायक रेसिडेंसी ऑयल मिल के पास बैतूल, जो भारतीय स्टेट बैंक से हेड कैशियर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया कि ठगी की शुरुआत 27 नवंबर 2025 को हुई, जब बसंत कुमार के मोबाइल पर

एक वॉट्सऐप वीडियो कॉल आया। कॉल स्क्रीन पर दिल्ली पुलिस लिखा दिखाई दिया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस अधिकारी बताया और दावा किया कि पीड़ित के आधार कार्ड से दिल्ली में एक सिम कार्ड जारी किया गया है, जिसका उपयोग ब्लैकमेलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में हुआ है। ठगों ने पीड़ित को यह भी बताया कि उनके खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने लगातार कॉल करके बसंत कुमार को मानसिक रूप से डराया और गिरफ्तारी से बचने तथा खातों की जांच के बहाने पैसे ट्रांसफर करने को कहा। डर के कारण, बसंत कुमार ने 1 दिसंबर 2025 को अपने एसबीआई खाते से 13.50 लाख रुपए यस बैंक खाते में और 10 लाख रुपए फिनो बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। उन्हें इस ठगी का पता तब चला जब वे बैंक में गोल्ड लोन लेने पहुंचे और बैंक प्रबंधक ने उन्हें धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी। इसके बाद, पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गंज थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डिजिटल अरेस्ट के पूर्व में भी आ चुके है मामले

गौरतलब है कि बैतूल जिले में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सारणी क्षेत्र में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने एक सेवानिवृत्त कोल कर्मी को ठगों के चंगुल से बचाकर 75 लाख रुपए की ठगी होने से रोका था। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं होती। कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी फोन या वॉट्सऐप कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे नहीं मांगती। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी अनजान कॉल या संदेश से भयभीत न हों और साइबर ठगी की आशंका पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम की वेबसाइड पर शिकायत दर्ज करें।

बिजली मेंटनेंस के कारण बंद रहेगी बिजली, शेड्यूल जारी

बैतूल। बिजली कंपनी द्वारा 7 जनवरी से 13 जनवरी तक अलग-अलग तिथियों में प्रातः10 से दोपहर 2 बजे तक 11 केव्ही लाइन का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जनवरी को 11 केव्ही खंजनपुर फीडर के मेंटेनेंस के चलते प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक खंजनपुर, अर्जुन नगर, टेलिफोन कॉलोनी, विकास नगर, कालापाठा, दुर्गा वार्ड, कत्तलढाना, सुयोग कॉलोनी, सरस्वती स्कूल, डिपो रोड आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। इसी प्रकार 8 जनवरी को 11 केव्ही ग्रीन सिटी फीडर के मेंटेनेंस के चलते प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक विनोबा नगर, विवेकानंद वार्ड, भग्गू ढाना, खादी उद्योग के पास, ग्रीन सिटी, माचन नगर, हमलापुर चौक, फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, जज कॉलोनी, मांझी नगर, तिवारी पेट्रोल पंप के पास के क्षेत्र में तथा 9 जनवरी को 11 केव्ही गंज के मेंटेनेंस के चलते प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक आबकारी, सिंधी कॉलोनी, देना बैंक, लोहिया वार्ड, तेल टंकी, लक्की सेंटर, कांति शिवा टॉकीज, सेंट्रल बैंक, एसबीआई बैंक, मैकेनिक चौक, अग्रवाल पेट्रोल पंप, बीजेपी कार्यालय, डॉ मूले, गुरुद्वारा रोड, हाथी नाला, डॉ.लश्करे, बीएसएनल ऑफिस, पुलिस क्वार्टर हाउसिंग बोर्ड, गंज महाराष्ट्र बैंक में विद्युत सप्लाई प्रभावित रहेगी। 10 जनवरी को 11 केव्ही काला पाठा फीडर के मेंटेनेंस के चलते प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक लोहिया वार्ड, चुन्नी ढाना, राजेंद्र वार्ड, सिविल लाइंस, संजय कॉलोनी, मुर्गी चौक, शिवाजी वार्ड, स्वीपर कॉलोनी, जेएच कॉलेज रोड तथा 12 जनवरी दिन सोमवार को 11 केव्ही रामनगर में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक गर्ग कॉलोनी, अचलपुर नाका, रामनगर, पटवारी कॉलोनी, जयप्रकाश वार्ड, खखरा जामठी तथा 13 जनवरी को 11 केव्ही सोना घाटी फीडर के मेंटेनेंस के चलते प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोसमी फाटक, सोना घाटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

महिला कांग्रेस ग्रामीण इकाई और रसोइया संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया

बैतूल। जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में अंशकालीन रसोइया चंपा वट्टी के आत्मदाह प्रयास के बाद विवाद बढ़ गया है। मंगलवार को महिला कांग्रेस ग्रामीण इकाई और रसोइया संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सहायक आयुक्त (एसी) ट्राइबल विवेक पांडे के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 20 रसोइयों को काम से हटाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि चंपा वट्टी पिछले 24 वर्षों से शासकीय वरिष्ठ आदिवासी बालक छात्रावास में अंशकालीन रसोइया के पद पर कार्यरत थीं। उन्हें हाल ही में बिना किसी लिखित आदेश के काम से हटा दिया गया था। इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने शनिवार को सहायक आयुक्त कार्यालय में मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। महिला कांग्रेस ग्रामीण की जिलाध्यक्ष लीला दवंडे ने आरोप लगाया कि जनजातीय कार्य विभाग में अंशकालीन कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा

है। उन्होंने कहा कि बैतूल आदिवासी बहुल जिला है, और विभाग के कुछ अधिकारी पद का दुरुपयोग कर आदिवासी वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ज्ञापन में सहायक आयुक्त विवेक पांडे के तत्काल स्थानांतरण और हटाई गई सभी रसोइयों को पुनः कार्य पर रखने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे छात्रों को समय पर भोजन और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जहां कर्मचारियों की कमी है, वहां तत्काल नियुक्तियां की जाएं और वेतन भुगतान में हो रही देरी को भी खत्म किया जाए। इस बीच, सहायक आयुक्त विवेक पांडे ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि कई छात्रावासों में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति और वेतन स्वीकृत नहीं है। ऐसे मामलों में केवल भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से करें निराकरण : कलेक्टर

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं आमजन की समस्याएं

बैतूल। बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, पेंशन, आवास, बिजली, पानी, भूमि विवाद सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। इस दौरान कलेक्टर ने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बैतूल मुख्यालय के टिकारी निवासी रोशनी कुंभारे ने सीमांकन के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित पटवारी को तत्काल सीमांकन करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि जनसुनवाई आम नागरिकों को राहत देने का प्रभावी माध्यम है। संबंधित विभागीय अधिकारी प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर समय पर समाधान सुनिश्चित करें। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर विभागीय जिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जन्म प्रमाण पत्र बनाने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में ग्राम चिखलीखुर्द निवासी कमलेश उबनारे ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को रोकने और कार्रवाई किए जाने के संबंध में आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने मुलताई के संबंधित अधिकारी को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। भैंसदेही के इंदिरा गांधी वार्ड निवासी कृष्णा बघेल ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। ग्राम बासनेरकला निवासी शशिकांत धाडसे ने सोसायटी के ऋण में छूट मिलने के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल के ग्राम जसोंदी निवासी अभिनय ने खेत के नक्शे को सुधारने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित राजस्व अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

अतिक्रमण हटाकर कब्जा दिलाने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में भैंसदेही तहसील के ग्राम आमला निवासी आवेदक ने भूमि का कब्जा दिलाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने भैंसदेही एसडीएम को तत्काल अतिक्रमण हटाकर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। बैतूल के लोहिया वार्ड निवासी उदय चौधरी ने आवेदन के माध्यम से स्कूल प्रिंसिपल द्वारा टीसी नहीं दिए जाने की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के डीईओ को टीसी दिलाने के निर्देश दिए। मुलताई तहसील के ग्राम लाखापुर निवासी नंदकिशोर खाचरे ने आवेदन के माध्यम से अंश के अनुसार बटवारा आदेश नहीं किए जाने की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित एसडीओ को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल के ग्राम चोरनी निवासी दिनेश धुर्वे ने अनावेदको के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।

कॉलेज चलो अभियान के प्रथम चरण में लगभग एक हजार विद्यार्थियों से किया संवाद

बैतूल। शासन के निर्देशानुसार जेएच कॉलेज द्वारा कॉलेज चलो अभियान के प्रथम चरण में अभियान दल द्वारा प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे के मार्गदर्शन में लगभग 30 शासकीय और अशासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों में पहुंचकर कक्षा 12वी के लगभग 1 हजार विद्यार्थियों के साथ संवाद किया गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभियान का प्रचार प्रसार किया गया। प्रथम चरण के अंतिम दौर में पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय बैतूल और संजीवनी स्कूल का भ्रमण किया गया। अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं यथा-ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, विषय चयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं, कौशल विकास पाठ्यक्रमों तथा शासन की विभिन्न छात्र हितकारी योजनाओं के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई।

ज्ञातव्य हो कि जिले के अग्रणी महाविद्यालय जेएच कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में

कुल 26 विषयों में अध्यापन सुविधा उपलब्ध है। पारंपरिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया सम्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर एआईसीटीई द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों बीबीए और बीसीए में प्रवेश हेतु तकनीकी शिक्षा संचलनालय के पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पंजीयन प्रक्रिया सम्पन्न होती है। शासन द्वारा पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, प्रतिभा किरण, गांव की बेटी योजना, मुख्यमंत्री संबल योजना, आवास योजना, मुख्यमंत्री मेधावी योजना इत्यादि के माध्यम से प्रतिभावान और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्र हितकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप शासन द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण सुविधाओं के साथ महाविद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत अभियान दल द्वारा विद्यार्थियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर अगले चरण में आवश्यक परिवर्तन के लिए फीडबैक भी प्राप्त किया किया गया है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मीनक्षी चौबे ने अभियान दल द्वारा प्रथम चरण प्रभावी रूप से आयोजित करने के लिए संयोजक प्रो राकेश कुमार पवार और उनके दल सदस्यों- प्रो दुर्गेश राने, प्रो मनेश मानेकर, प्रो संतोष पवार, डॉ. महेंद्र नावंगे, डॉ शारदा द्विवेदी, प्रो हितेश जैन, प्रो राज वाघमारे, डॉ. कंचन गुजरे, डॉ निहारिका भावसर, कीर्ति वराठे को बधाई देते हुए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से अनुरोध किया कि वे प्रवेश पूर्व विद्यार्थियों को परिसर विजिट जरूर कराएं और महाविद्यालय में स्थापित हेल्प सेंटर के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करें।

संवेदनशील सोच, सशक्त कदम, शांति और विश्वास की पहचान-मप्र पुलिस

नक्सल-मुक्त क्षेत्रों से लेकर जनकेंद्रित, तकनीक-आधारित सुरक्षा तक

सय्यद असीम अली

मध्यप्रदेश पुलिस ने वर्ष 2025 में कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सरोकार और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और सशक्त दिशा-निर्देशन में प्रदेश पुलिस ने न केवल अपराध नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाई, बल्कि नागरिकों के प्रति संवेदनशील, तकनीक-आधारित और भरोसेमंद पुलिसिंग का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

महिला-बाल एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा में प्रभावी पहल

वर्ष 2025 में संचालित ऑपरेशन मुस्कान एवं मुस्कान विशेष अभियान के तहत मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशभर से 14 हजार से अधिक गुमशुदा नाबालिग बालक-बालिकाओं को सुरक्षित दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाया। उल्लेखनीय है कि यह अभियान केवल प्रदेश तक सीमित न रहकर अन्य राज्यों तथा नेपाल-पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों तक विस्तारित रहा। इसी तरह सृजन अभियान के अंतर्गत 5 हजार से अधिक बालक-बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया, जिससे बाल विवाह, बाल हिंसा जैसे गंभीर सामाजिक अपराधों की रोकथाम में ठोस परिणाम सामने आए।

अपराधों पर कड़ा अंकुश

अवैध हथियारों के निर्माण, तस्करी और उपयोग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 2,266 फायर आर्म्स और 4,800 धारदार हथियार जब्त किए गए। अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोहों का पर्दाफाश कर अवैध फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया गया।

चोरी, लूट एवं डकैती के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 132 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चोरी की संपत्ति बरामद की गई। चोरी गए वाहनों की बरामदगी में 3,779 दोपहिया, 274 चारपहिया तथा 193 अन्य वाहन शामिल हैं।

जहाँ डर टूटा,भरोसा बना

वर्ष 2025 मध्यप्रदेश पुलिस के लिए केवल उपलब्धियों का नहीं, बल्कि विश्वास निर्माण का वर्ष रहा। मध्यप्रदेश पुलिस ने बीते वर्ष में अपनी कार्यशैली से यह सिद्ध किया है कि सख्त कानून-व्यवस्था और मानवीय संवेदनशीलता साथ-साथ चल सकती हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति की बहाली, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई ने जनता के मन से डर को दूर किया है। जनसंवाद, तकनीकी नवाचार और पारदर्शी प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से पुलिस और समाज के बीच विश्वास की नई मजबूत कड़ी बनी है। आज मध्यप्रदेश पुलिस केवल सुरक्षा बल नहीं, बल्कि भरोसे का ऐसा स्तंभ बन चुकी है, जिस पर समाज निडर होकर आगे बढ़ रहा है।

नक्सल उन्मूलन से लेकर साइबर अपराध नियंत्रण तक पुलिस ने सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलित उदाहरण प्रस्तुत किया। ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से हजारों गुमशुदा बच्चों की सुरक्षित वापसी, नशे से दूरी है ज़रूरी जैसे जनआंदोलनों और डिजिटल पुलिसिंग ने जनता का भरोसा मज़बूत किया। डायल-112, साइबर हेल्पलाइन और तकनीकी नवाचारों से पुलिस की पहुँच तेज़ और पारदर्शी बनी। मध्यप्रदेश पुलिस ने साबित किया कि जब सुरक्षा के साथ संवाद जुड़ता है, तब डर टूटता है और विश्वास जन्म लेता है।

सुनती है, समझती है, साथ निभाती है

मध्य प्रदेश पुलिस आज केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी बन चुकी है। बदलते समय के साथ पुलिस की भूमिका संवाद, संवेदनशीलता और सहयोग की दिशा में विस्तृत हुई है। जनसुनवाई, थाना स्तर पर संवाद कार्यक्रम, पुलिस चौपाल, महिला व साइबर सुरक्षा अभियान और सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस आम नागरिकों से सीधे जुड़ रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और समस्याओं के समाधान में तेजी आई है। महिला एवं बाल सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, हेल्पलाइन और विशेष सहायता डेस्क ने पीड़ितों का भरोसा मजबूत किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ने दूर-दराज़ के लोगों तक पुलिस की पहुँच आसान बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस चौपाल और युवाओं के लिए संवादात्मक कार्यक्रम समाज में सहयोग और सुरक्षा की भावना को सशक्त कर रहे हैं।

नक्सल उन्मूलन में ऐतिहासिक सफलता

वर्ष 2025 मध्यप्रदेश के लिए नक्सलवाद उन्मूलन की दृष्टि से ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। तीन दशकों पुरानी नक्सल समस्या का योजनाबद्ध समाधान करते हुए प्रदेश को पूरी तरह नक्सल-मुक्त घोषित किया गया। बालाघाट, मंडला सहित प्रभावित जिलों में हार्डकोर नक्सलियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई हुई। कई इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ों में मार गिराया गया तथा आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2023 के अंतर्गत नक्सलियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया। इन कार्रवाइयों में शामिल 64 वीर पुलिसकर्मियों को क्रमोन्नति प्रदान की गई।

साइबर अपराध एवं डिजिटल सुरक्षा

'सेफ क्लिक' पहल के माध्यम से डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा को सशक्त किया गया। नागरिकों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार, फर्जी लिंक, एप्स, डिजिटल फ्रॉड, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं एनसीआरपी पोर्टल की जानकारी दी गई। साइबर फ्रॉड मामलों में त्वरित कार्रवाई कर नागरिकों की 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षित वापस कराई गई। संगठित साइबर ठगी गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज की गई।

नशामुक्त समाज की दिशा में जनआंदोलन

'नशे से दूरी है ज़रूरी' अभियान के तहत प्रदेशभर में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 15 हजार से अधिक कार्यक्रमों में 22 लाख से अधिक नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता रही, वहीं 22 लाख से अधिक लोगों ने नशामुक्त समाज के लिए शपथ ली। सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान को 10 करोड़ से अधिक व्यूज़ प्राप्त हुए।

इस दौरान 1 अरब 93 लाख रुपये से अधिक के अवैध मादक पदार्थ एवं 55 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई। एसटीएफ द्वारा हजारों किलोग्राम गांजा पकड़कर तस्करी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया गया।

जनसुरक्षा, त्वरित सेवाओं, तकनीकी नवाचार और प्रशासनिक सुधारों का सशक्त समन्वय

डायल-112 के अंतर्गत 1200 एफआरवी वाहनों का संचालन प्रारंभ किया गया, जिससे आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित पहुँच सुनिश्चित हुई। सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से 31,519 गुम मोबाइल फोन खोजकर उनके मालिकों को लौटाए गए। मध्यप्रदेश पुलिस ने e-HMRS, e-Office और ICJS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू कर कार्यप्रणाली को पारदर्शी, डिजिटल और पेपरलेस बनाया। MANIT, भोपाल के साथ Mo के तहत Center of E&cellence for Public Safety की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिससे भविष्य की पुलिसिंग को और अधिक तकनीक-आधारित एवं मानवीय बनाया जा सके।

सम्मान और उपलब्धियाँ

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा को हैप्पीनेस संस्था द्वारा 'हैप्पीनेस चेंज मेकर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।

'नशे से दूरी है ज़रूरी' अभियान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली।

राजधानी से सीमावर्ती इलाकों तक, सुरक्षा का मजबूत कवच

राजधानी भोपाल से लेकर सीमावर्ती और दूरस्थ अंचलों तक मध्यप्रदेश पुलिस ने वर्ष 2025 में सशक्त सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की। नक्सल उन्मूलन, अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और जनसंवाद के माध्यम से पुलिस ने पूरे प्रदेश में भरोसे और सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार किया है। मध्यप्रदेश पुलिस ने नशामुक्ति, महिला-बाल संरक्षण और तकनीकी नवाचार के माध्यम से न केवल प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि नागरिकों के बीच सुरक्षा का विश्वास और पुलिस-जन संवाद को भी नई मजबूती प्रदान की है।

मध्य प्रदेश पुलिस ने यह साबित किया है कि प्रभावी कानून-व्यवस्था जनता के विश्वास और सहभागिता से ही संभव है। संवाद और संवेदनशीलता के इन प्रयासों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस वास्तव में सलाम के योग्य है।

कॉलेज चलो अभियान के तहत विद्यालयों का भ्रमण

विदिशा (निप्र)। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सत्र 2026-27 के लिए राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा द्वारा कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण किया गया। यह अभियान पांच दिसंबर से शुरू हुआ जो पांच जनवरी 2026 तक संचालित किया जा रहा है। कॉलेज चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यालयीन छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी देना, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को समझाना तथा महाविद्यालय में उपलब्ध व्यावसायिक एवं पारंपरिक पाठ्यक्रमों से अवगत कराना है। इसके साथ ही छात्राओं को महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों, कोर्सों, शैक्षणिक वातावरण एवं सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा जिले का एक अग्रणी महाविद्यालय है, जहाँ वर्तमान में लगभग 6 हजार छात्राएँ अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय में भूगोल, इतिहास, संगीत, कंप्यूटर, गृह विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु एनसीसी, एनएसएस एवं खेल मैदान जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। महाविद्यालय की टीम द्वारा विद्यालयों में भ्रमण के दौरान छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई, जिससे अधिक से अधिक छात्राएँ उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित हो सकें। कॉलेज चलो अभियान का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बी. डी. अहिरवार, संस्था प्रमुख के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। अभियान की नोडल अधिकारी डॉ. विनीता प्रजापति द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, विदिशा से समन्वय स्थापित कर जिले के सभी विद्यालयों में महाविद्यालय टीम के साथ भ्रमण कर अभियान को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया।

नगर पालिका विदिशा द्वारा पेयजल गुणवत्ता की रैंडम सैंपलिंग अभियान

विदिशा (निप्र)। नगरपालिका विदिशा द्वारा शहरवासियों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेयजल गुणवत्ता की रैंडम सैंपलिंग अभियान संचालित किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार ठाकुर ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत नगर के विभिन्न वार्डों में प्रदाय किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच की गई। अभियान के दौरान अमृत मित्रों के माध्यम से वार्ड क्रमांक 18, 29 एवं 34 के विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर पेयजल के नमूने एकत्र किए गए। एकत्रित नमूनों की जांच मौके पर ही निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप की गई। जांच प्रक्रिया में पेयजल की गुणवत्ता को टर्बिडिटी (मटमैलेपन), कलर (रंग), टीडीएस सहित अन्य निर्धारित भौतिक एवं रासायनिक मानकों पर परखा गया। नगर पालिका द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि सभी नमूनों की जांच पारदर्शी एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप हो। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की रैंडम सैंपलिंग से पेयजल की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, जिससे समय रहते आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और नागरिकों को स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। भविष्य में भी नियमित रूप से इस तरह के परीक्षण अभियान जारी रहेंगे।

एनसीसी की पीएम साइकिल रैली विदिशा पहुंची

विदिशा (निप्र)। भारत में एनसीसी कैडेट्स द्वारा प्रतिवर्ष कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका शुभारंभ एनसीसी पीएम रैली के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाता है। एनसीसी पीएम रैली 2026 के अंतर्गत एनसीसी निदेशालय महाराष्ट्र द्वारा 'शौर्य के कदम, क्रांति की ओर' नामक एक विशेष साइकिल अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान ऐतिहासिक दृष्टि से वर्ष 1736 में मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा दिल्ली पर किए गए आक्रमण के मार्ग पर आधारित है। यह साइकिल रैली पुणे से नई दिल्ली तक आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति एवं ऐतिहासिक गौरव का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। अभियान में एनसीसी ग्रुप अमरावती के 12 कैडेट्स शामिल हैं, जो ब्रिगेडियर सचिन गवली, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय अमरावती के नेतृत्व में पूरे मार्ग की साइकिल टीम का हिस्सा हैं।

टीम के साथ 6 सदस्यों की कोर सपोर्ट टीम भी कार्यरत है। यह अभियान कुल 1680किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो पांच राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगा, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसे 21 साइकलिंग दिनों में पूर्ण करने की योजना है। एक्सपेडिशन का शुभारंभ 24 दिसंबर 2025 को पुणे के वाड़ा से हुआ, जो 4 जनवरी 2026 को विदिशा पहुंचा है और 16 जनवरी 2026 को दिल्ली पहुंचेगा। 26 जनवरी 2026 को एनसीसी पीएम रैली 2026 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान को फ्लैग-इन किया जाएगा। अब तक टीम 11 साइकलिंग दिनों में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एनसीसी डायरेक्टरेट के अंतर्गत विदिशा जिले में इस साइकिल रैली का भव्य स्वागत 14 एमपी बटालियन एनसीसी विदिशा द्वारा किया गया। यह आयोजन कमान अधिकारी कर्नल विकास गुप्ता (शौर्य चक्र) के निर्देशानुसार तथा प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सनी वैद्य के मार्गदर्शन एवं संयोजन में संपन्न हुआ। साइकिल रैली की अगवानी एवं स्वागत विदिशा जिले के पुलिस अधीक्षक श्री रोहित केसवानी एवं लेफ्टिनेंट कर्नल सनी वैद्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर सचिन गवली को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। रैली में 11 महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विजय भी शामिल रहे।

गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज एवं सेंट मैरी पीजी कॉलेज, विदिशा की एनसीसी कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से साइकिल रैली का उत्साहवर्धन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन लेफ्टिनेंट डॉ. विनीता प्रजापति द्वारा तथा कार्यक्रम का संचालन कैप्टन रामानंद मिश्रा द्वारा किया गया। 14 एमपी बटालियन के समस्त पीआई स्टाफ ने रैली दल का स्वागत, अभिनंदन एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया।

जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के के निर्देशानुसार जिले के सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस प्रक्रिया से जुड़ सकें। ग्राम बैजनाथ, ग्राम कौड्यानाथू, लाऊखेड़ी , ग्राम निपानिया कला, ग्राम चुपाडीया, ग्राम डाबरी, ग्राम पगारिया राम, ग्राम खाचरोद, ग्राम डेंडी, ग्राम काजीखेड़ी, ग्राम बकतरा, ग्राम दरखेड़ा, ग्राम चनोठा, ग्राम मालीपुराग्राम बजाखेड़ी, ग्राम सेवनिया सहित अनेक गांवों में कैंप लगाए गए। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं एवं लाभों का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि कैंप के दौरान किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के महत्व की जानकारी दें और उन्हें रजिस्ट्री कराने के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी ग्राम पंचायत में आयोजित कैंप में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी शासकीय योजना या सुविधा का लाभ प्राप्त करने में उन्हें कोई कठिनाई न हो।

नर्मदापुरम में युवक की हत्या कर नदी में फेंका शव

शुगर मिल के पीछे मिली लाश; 7 दिन से लापता था, गला दबाकर मारा

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के बनखेड़ी में शुगर मिल के पीछे ओल नदी में रविवार को एक युवक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त सेवक उर्फ शिवा कहार (23) के रूप में हुई है। वह पिछले 7 दिनों से लापता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि युवक की हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक सेवक उर्फ शिवा जुनेहटा का रहने वाला था और रायसेन जिले के सांईखेड़ा में मजदूरी करता था। वह 28 दिसंबर से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी सांईखेड़ा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था।

6-7 दिन पुरानी है लाश, फोटो से हुई पहचान

रविवार शाम को बनखेड़ी में ओल नदी में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव करीब 6-7 दिन पुराना बताया जा रहा है। बनखेड़ी थाना प्रभारी विजय सनस ने बताया कि पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने गला दबाने से मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने शव की फोटो आसपास के थानों और सोशल मीडिया पर भेजी, जिसके बाद उसकी पहचान हो सकी। पुलिस अब हत्यारों की तलाश में जुट गई है।

कनारा लेदर बाल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ

विदिशा (निप्र)। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल ने रविवार को कनारा लेदर बाल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज छोटे-छोटे शहरों और कस्बों से भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलकर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और समर्पण से खेलों के क्षेत्र में उच्च मुकाम हासिल किया जा सकता है। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि लगातार 56 वर्षों से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन होना इस बात का प्रतीक है कि आयोजकों, खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों के सामूहिक प्रयास से यह परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए आयोजक समिति को बधाई देते हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस अवसर पर विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन ने कहा कि जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले में अंतरराष्ट्रीय मानकों का क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने हेतु भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया जारी है। कनारा क्लब के सचिव श्री नागेन्द्र सिंह लोधी ने टूर्नामेंट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए इस वर्ष के आयोजन की रूपरेखा और विशेषताओं की जानकारी दी।

अनावरण व शुभारंभ : प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल ने कनारा लेदर बाल क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया तथा स्वयं मैदान पर बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आयोजक समिति के पदाधिकारी, टूर्नामेंट में भाग ले रही विभिन्न टीमों के खिलाड़ी, गणमान्य नागरिक, दर्शकगण एवं मीडिया प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

स्व. लक्ष्मीकांत शर्मा स्मृति में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन

हरेक विधानसभा क्षेत्र में बनेगा स्टेडियम - प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल

विदिशा (निप्र)। स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा की स्मृति में आयोजित लेदर बाल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में जिले के प्रभारी मंत्री एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री श्री लखन पटेल शामिल हुए। इस अवसर पर खेलप्रेमियों एवं खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। सिरोंज विधायक श्री उमाकांत शर्मा ने प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल का अभिनंदन किया तथा खेल मैदान स्थित सांदीपनि स्कूल में आयोजित फाइनल मुकाबले की दोनों टीमों के खिलाड़ियों से सौजन्यात्मक परिचय प्राप्त कर उन्हें श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने खेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अभ्यास एवं प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त अवसर एवं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवा समान रूप से खेल सुविधाओं का लाभ उठाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें।

प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार एवं खेल विभाग प्रदेश में सभी प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले नामी खिलाड़ी बड़े शहरों से ही निकलते थे, लेकिन अब सरकारी प्रोत्साहन के कारण छोटे गांवों और कस्बों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी क्रांति गौंड का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक श्री उमाकांत शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के लटेरी में संपूर्ण सुविधायुक्त खेल मैदान तथा सिरोंज के सांदीपनि स्कूल मैदान के समीप पुराने शनिचरा नाले पर स्टेडियमनुमा सीढ़ियों के निर्माण की मांग रखी। इस पर प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल ने घोषणा करते हुए खेल मंत्रालय के माध्यम से चार करोड़ रुपये की लागत से इनडोर स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की बात कही और कहा कि विधायक द्वारा प्रस्तावित स्थान पर यह निर्माण कराया जाएगा।

सांदीपनि स्कूल मैदान में आयोजित फाइनल मुकाबले में गुना की साईं क्रिकेट क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जबकि महाराष्ट्र के जलगांव की जुनैद क्रिकेट क्लब उपविजेता रही। समारोह में माधव ग्रुप के संरक्षक श्री राहुल त्यागी द्वारा प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल एवं विधायक श्री उमाकांत शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता, उपविजेता एवं व्यक्तिगत पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया।

राइट क्लिक

इन 'डिजिटल बंजारों' की बात मत पूछो जी... !

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

तीन दशक पहले तक इस देश में 'हड़ताल' ऐसा शब्द था, जिसकी गूंज और असर व्यापक होता था। सरकारी, अर्द्धसरकारी दफ्तरों और कपड़ा मिलों आदि में आए दिन हड़तालें होती रहती थीं। समाजवादी नीतियों में हड़ताल को श्रमिक का अधिकार माना जाता रहा है, जिसका वो भरपूर उपयोग करते थे। बल्कि कई बार तो यह सवाल पूछा जाता था कि सरकारी दफ्तरों में हड़ताल के अलावा काम कब होता है? लेकिन नई आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद हड़ताल भी अब विरल शब्द हो गया है। अलबत्ता बीते साल के आखिरी दो दिनों में देश भर में हुई एक हड़ताल ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा। ये वो लोग थे, जिन्हें लोग पहचानते तो हैं, लेकिन उनकी कठिन जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। बल्कि उनके साथ उनके नियोक्ताओं और कस्टमर का व्यवहार भी गुलामों की माफिक होता है। ये हैं-गिग वर्कर। दो दशक पहले इन गिग कर्मचारियों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन ऐप आधारिक क्विक कॉमर्स कंपनियों का जमाना आया तो लाखों युवा (जिन्हें राइडर कहा जाता है) रोजगार की मजबूरी में 'जो हुक्म मेरे आका' की तर्ज पर काम करने लगे। गिग वर्कर को स्वंतत्र ठेकेदार, ऑन लाइन प्लेटफार्म वर्कर्स अथवा ऑन डिमांड वर्कर भी कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें डिजीटल बंजारा भी कहते हैं।

हाल में इन्होंने अपने काम की बेहतर परिस्थितियां और ज्यादा पारिश्रमिक की मांग को लेकर दो दिन हड़ताल की थी। दावा था कि इससे देश में फूड डिलीवरी सिस्टम बैठ जाएगा। कहा गया कि इसमें 70 हजार से ज्यादा गिग वर्करों ने भाग लिया। हालांकि उसका ज्यादा असर नहीं हुआ और उनकी नियोक्ता कंपनियों ने हड़ताल को फेल बताया। दरअसल आजकल दो शब्द हमारे दैनंदिन शब्दकोश का हिस्सा बन गए हैं, ये हैं-डिलीवरी ब्वॉय और कैब ड्राइवर। कर्मचारियों की यह ऐसी जमात है, जो न तीन में है और न तेरह में। यानी वो न तो कंपनी के नियमित कर्मचारी हैं और न ही दिहाड़ी मजदूर। नियोक्ता कंपनियां इन्हें ' डिलीवरी पार्टनर' कहती हैं और ऑर्डर की डिलीवरी के हिसाब से पैसा देती हैं। कहने को यह 'पार्टनर' हैं, लेकिन हकीकत में उनकी हैसियत 'बिजेनस लिव-इन पार्टनर' से भी बदतर है। कस्टमर ने जरा भी शिकायत की तो डिलीवरी पार्टनर की आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। डिलीवरी निर्धारित समय में करने की मजबूरी के चलते जान का जोखिम बना ही रहता है। यूं 'गिग' शब्द का निश्चित अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। अंग्रेजी में मोटे तौर पर इसका मतलब 'वो कोई भी काम जिसके बदले में भुगतान किया जाता से हो' से है।' आधिकारिक तौर पर गिग शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी उपन्यासकार जैक केरोऑक ने 1952 में वहां के रेलवे ब्रेकमैन के लिए किया था। लेकिन गिग वर्करों की तस्वीर सन 2000 में तब साफ हुई, जब दुनिया में आर्थिकी का डिजीटल कायांतरण होने लगा। इंटरनेट और स्मार्टफोन इसके मुख्यो टूल बने। यानी आप किसी भी क्विक कॉमर्स कंपनी के लिए ऑर्डर बुक करिए और दस मिनट में इच्छित माल हाजिर। वस्तु की पैकिंग और उसे ग्राहक तक यथाशीघ्र डिलीवर कराने का काम गिग वर्करों का होता है। कुछ ऐसी ही स्थिति कैब ड्राइवरों की है। लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि जो इस व्यवस्था के सूत्रधार हैं, खुद उनकी जिंदगी क्या है? क्विक कॉमर्स अथवा ट्रैवल एजेंसियों के लिए ग्राहक भगवान है, लेकिन उसे संतुष्ट रखने वाला गिग वर्कर कंपनी और कस्टमर दोनो का गुलाम है। गिग वर्करों का जॉब फुल टाइम है, क्योंकि कब किस कंपनी का कहां से सप्लाई ऑर्डर आ जाए अथवा कब कौन कहां के लिए कैब बुक कर दे, कहा नहीं जा सकता। ग्राहक के लिए दिन और रात बराबर होते हैं। उसकी सोच है कि चूंकि वह पैसा फेंक रहा है, इसलिए उसे सब मनमाफिक चाहिए।

जहां सेवा शर्तों की बात है तो गिग वर्कर्स नौ से पांच की पक्की नौकरी के बजाय अस्थायी, लचीले समय अवधि वाले या फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। इन्हें हर काम के लिए अलग-अलग पेमेंट मिलता है। जितना काम करते हैं, उतना मेहनताना मिलता है। लेकिन तस्वीर उतनी सहज नहीं है, जितनी दिखाई पड़ती है। इन्हीं गिग वर्करों की यूनियन तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPW) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने विगत 25 व 31 दिसंबर को हड़ताल का आव्हान किया था। उसे तोड़ने के लिए स्विगी और जोमैटो ने कंपनियों ने पीक ऑवर्स और ईयर-एंड डेज पर ज्यादा इंसेंटिव देने का ऐलान भी किया। फिर भी गिग कर्मचारी उस प्रतिरोध को सफल मानते हैं। हालांकि उनकी नाराजी केन्द्र सरकार की भूमिका को लेकर भी है। यूनियन के मुताबिक ऐप कंपनियां कर्मचारियों को 'पार्टनर' बताकर श्रम कानूनों से बच रही हैं। यह भी तय नहीं है कि वो कर्मचारी हैं या स्वतंत्र ठेकेदार। गिग कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं से W-2 फॉर्म मिलता है, जिसके तहत वो कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने, वेतन कर काटने, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने और भेदभाव-विरोधी कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके विपरीत, स्वतंत्र ठेकेदारों को 1099 फॉर्म प्राप्त होते हैं, जब वे किसी कंपनी के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं होते हैं।

वैसे गिग वर्कर्स की हालिया हड़ताल का इतना लाभ तो हुआ कि केन्द्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत एक नया ड्राफ्ट पेश किया। इस सर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार की मंशा जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, समेत तमाम प्लेबटफॉर्म के डिलीवरी ब्वॉटयज तथा ओला-उबर कैब ड्राइवर को सोशल सिक्योमरिटी दायरे में लाना है। पहली बार गिग वर्कर को श्रमिक'की श्रेणी में लाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने विगत 21 नवंबर 2025 को चार नई श्रम संहिताएं नोटिफाई की थीं, जिनमें गिग वर्करों का भी उल्लेख था। नए प्रस्ताव के तहत देश में गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से प्राप्त योगदान जमा होगा। यदि कोई कंपनी तय समय पर निश्चित योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। सामाजिक सुरक्षा पाने के लिए गिग वर्कर को किसी कंपनी के साथ साल भर में कम-से-कम 90 दिन काम करना होगा। दूसरे, अगर इस अवधि में वह एक से अधिक ऐप या कंपनियों के साथ काम करता है, तो कुल मिलाकर उसे न्यूनतम 120 दिन काम करना होगा। तीसरे, गिग वर्कर को किसी दिन चाहे जितनी भी कमाई हुई हो, यदि काम किया है तो उसे एक कार्यदिवस माना जाएगा। चौथे, अगर कोई डिलीवरी पार्टनर या कैब ड्राइवर किसी दिन ऐप के जरिये एक भी ऑर्डर या सफर को पूरा करता है, तो वह दिन उसके कामकाजी दिन के रूप में गिना जाएगा। पांचवा, यदि कोई व्यक्ति एक ही दिन में तीन अलग-अलग ऐप के लिए काम करता है, तो उसे तीन दिन का काम माना जाएगा। इसके अलावा हर कंपनी को अपने साथ जुड़े अस्थायी कामगारों की जानकारी नियमित रूप से सरकारी पोर्टल पर अद्यतन करनी होगी। 16 साल या उससे अधिक उम्र के हर अस्थायी कामगार को 'आधार' जैसे दस्तावेजों के आधार पर एक निर्धारित पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें एक डिजिटल पहचान पत्र मिलेगा, जिसे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

हालांकि क्विक कॉमर्स कंपनियां गिग वर्करों के शोषण से इंकार करती है। जोमैटो की कंपनी इटरनल के सीईओ दीपेंदर गोयल के अनुसार डिलीवरी पार्टनरों का किसी तरह कोई शोषण नहीं हो रहा है। हड़ताल शरारती तत्वों ने कराई थी। इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी थे। उन्होंने 10 मिनट में डिलीवरी के वादे को भी तर्कसंगत बताया। बहरहाल भारत में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। नीति आयोग ने 2022 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। इनमें एप बेस्ड कैब ड्राइवर से लेकर डिलीवरी एजेंट तक शामिल हैं। आयोग का अनुमान है कि 2030 तक इन वर्कर्स की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इनमें करीब 30 फीसदी महिलाएं हैं, जिनकी कार्य परिस्थितियां और भी कठिन हैं। महिला गिग वर्करों के लिए अलग से वॉशरूम भी नहीं होते।

इसी तरह 'एक्शन एंड मूवमेंट' और 'इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स' ने साथ मिलकर भारत में गिग वर्कर्स पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। नाम था-'Prisoners on Wheels'। रिपोर्ट के मुताबिक, 31त्न एप बेस्ड कैब ड्राइवर 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। अधिकांश को साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती। खर्चे काटकर वो दिन में 500 से 1000 रू. तक कमा पाते हैं। सर्वे में चौंकाने वाली जानकारी यह थी कि गिग वर्करों में करीब 62 प्रतिशत दलित और 60 प्रतिशत आदिवासी ड्राइवर हैं, जो दिन में 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। इनके मुकाबले जनरल कैटेगरी के 16 प्रतिशत और ओबीसी कैटेगरी के 26 प्रतिशत ड्राइवर ही इतनी देर काम करते हैं।

देश में राजस्थान और कर्नाटक ने सबसे पहले गिग वर्कर्स पर ध्यान देकर उनके हित कानून में बनाए हैं। लेकिन गिग कर्मचारियों के मिनिमम वेज, काम के घंटे और दूसरी मांगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ऊपर से कंपनी के वादे के मुताबिक दस मिनट में यदि डिलीवरी नहीं हुई और कस्टमर इसकी शिकायत कर दे तो नुकसान गिग वर्कर को अपनी जेब से भरना पड़ता है। यही नहीं, ऑर्डर डिलीवरी के लिए आने-जाने के परिवहन खर्च में भी एकरूपता नहीं है। हालांकि कंपनियां ऑर्डर पूरा करने पर इंसेंटिव भी देती हैं, लेकिन इसकी शर्तें पूरी करना आसान नहीं होता। इसके पहले कि रोजगार का यह सेक्टर मर्ज बन जाए गिग वर्करों पर अभी से गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है, उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा इस क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं।

दूषित पानी से 17 मौतें, हाईकोर्ट बोला

इंदौर की छवि धूमिल, सरकार का जवाब असंवेदनशील

जरूरत पड़ी तो अफसरों पर तय होगी क्रिमिनल जिम्मेदारी

भोपाल/इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को दूषित पेयजल से जुड़े मामले में 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा- इस घटना ने इंदौर शहर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब दूषित पानी की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी। साथ ही संकेत दिए कि अगर पीड़ितों को मुआवजा कम मिला है तो उस पर भी अदालत उचित निर्देश जारी करेगी।

अब तक 17 लोगों की मौत, 110 भर्ती

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को उल्टी-दस्त के 38 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6 मरीजों को अरबिंदो अस्पताल रेफर किया गया है। इन्हें मिलाकर कुल 110 मरीज अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। बीमार होने के बाद कुल 421 मरीजों को अस्पताल लाया गया था, इनमें से 311 डिस्चार्ज हो चुके हैं। आईसीयू में 15 मरीजों का इलाज जारी है।

शिकायतों पर ध्यान देते तो मौतें नहीं होतीं- मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि 31 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को स्वच्छ

पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रभावित इलाकों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि प्रशासन ने पहले की गई शिकायतों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया। यदि ऐसा किया जाता तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी, जिसमें मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

भागीरथपुरा बना अभेद किला, कांग्रेस नेताओं को जाने से रोका तो जीतू पटवारी ने कहा- तालिबान राज है क्या?

भागीरथपुरा में दूषित जल से अभी तक 17 मौतें हुई हैं। इसे लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेता भागीरथपुरा पहुंचे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी। भागीरथपुरा के आसपास बैरकेडिंग की गई थी। साथ ही वॉच टावर बनाए गए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। भागीरथपुरा की घेरेबंदी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है। तालीबान राज है क्या?

सिर्फ आठ नेताओं को अंदर जाने की अनुमति

दरअसल, भागीरथपुरा में धरना, प्रदर्शन और सभा पर प्रतिबंध है। कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। साथ ही भागीरथपुरा के लोगों से मिलना चाहते थे। प्रशासन ने मात्र आठ बड़े नेताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। इसके बाद प्रदेश जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत आठ नेता कॉलोनी के अंदर गए। साथ ही पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उनसे बातें की है।

बैरिकेड के दौरान बहसबाजी भी हुई- इंदौर पुलिस ने बैरिकेड कर कांग्रेस नेताओं का रास्ता रोक दिया था। वहीं, नेता आगे बढ़ना चाहते थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी बहसबाजी भी हुई है। अपने लोगों को जीतू पटवारी ने वॉच टावर पर चढ़कर संबोधित भी किया है।

सबसे पहले 2 बच्चों में मिले थे हैजा जैसे सिम्टम्स

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 17 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि समय रहते बच्चों में हैजा जैसे सिम्टम्स पता चल गए, नहीं तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। सबसे पहले भागीरथपुरा के दो बच्चों में हैजा जैसे सिम्टम्स मिले थे। पहला बच्चा 28 दिसंबर को सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया था। सरकारी लैब में उसकी जांच के दौरान हैजा जैसे लक्षण मिलने की पुष्टि हुई थी।

जान बचाने के लिए भागीरथपुरा से पलायन शुरू, घरों में ताला लगाकर गांवों की ओर भागे लोग

इंदौर के भगीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई बर्बादी के बाद, तीन परिवार बिना किसी इंतज़ार के अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं। घटना के बाद से अब लोग नर्मदा का पानी पीने से कतराते हैं और महंगे आरओ या टैंकर का पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही एक परिवार के मुखिया सुरेंद्र रावत, जो एक औद्योगिक इलाके में मजदूरी करते हैं, ने 31 दिसंबर को अपने एक कमरे के किराए के मकान में ताला लगाया और सागर जिले के अपने गांव शाहपुर के लिए बस पकड़ ली। सुरेंद्र ने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गई थी। बेटी के इलाज में उनके करीब 10,000 रुपये खर्च हो गए, जो उनकी सारी बचत थी।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल से नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने आज लोकभवन में सौजन्य भेंट की।

पीटी करते वक्त छठवीं की छात्रा गिरी, फिर नहीं उठी

बदनावर (धार) (नप्र)। धार जिले के बदनावर में जवाहर नवोदय विद्यालय मुलथान में मंगलवार सुबह एक छात्रा की अचानक मौत हो गई। छठवीं क्लास में पढ़ने वाली निशा सूर्यवंशी (13) की स्कूल ग्राउंड में पीटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

निशा रोज की तरह सुबह पीटी के लिए बाकी बच्चों के साथ ग्राउंड पर गई थी। सुबह करीब सवा 7 बजे वह पीटी करते-करते अचानक गिर पड़ी। ग्राउंड पर मौजूद बच्चों और टीचर्स ने उसे संभाला। शरीर में कोई हलचल नहीं होने पर उसे फौरन सिविल अस्पताल, बदनावर ले गए।

अस्पताल में डॉक्टरों ने चेकअप के बाद निशा को मृत घोषित कर दिया। तहसीलदार सुरेश नागर भी सिविल अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया।

20 साल की मादा तेंदुआ 'पन्ना' की मौत

5 साल पहले रेस्क्यू कर लाई गई थी, वृद्धावस्था के चलते तोड़ा दम

मैहर (नप्र)। विंध्य की शान कहे जाने वाले मध्यप्रदेश के मैहर जिले में स्थित महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू (मुकुंदपुर) से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पिछले 5 सालों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही मादा तेंदुआ (पन्ना) की मौत हो गई है। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, जो तेंदुओं की औसत उम्र से काफी ज्यादा मानी जाती है। जू प्रबंधन के मुताबिक, मादा तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 2 जनवरी की सुबह उसने दम तोड़ दिया है।

2020 में पन्ना के जंगलों से किया था रेस्क्यू- इस मादा तेंदुआ का मुकुंदपुर तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा था। इसे 12 दिसंबर 2020 को दक्षिण पन्ना वनमंडल के मोहन्द्रा परिक्षेत्र की बीट जमुन्हा से रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद इसे मुकुंदपुर जू लाया गया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली ने 4 मार्च 2025 को इसे विधिवत रूप से मुकुंदपुर जू में रखने की अनुमति प्रदान की थी।

डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा था इलाज- जू के वन्यप्राणी चिकित्सक डॉ. नितिन गुप्ता ने बताया कि वृद्धावस्था के कारण मादा तेंदुआ के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। उसे निरंतर निगरानी में रखकर उपचार दिया जा रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी सेहत नहीं सुधरी और 2 जनवरी 2026 को सुबह करीब 6:48 बजे उसने दम तोड़ दिया।

17 मौतें, 4 मुआवजे, भाजपा की असंवेदनशीलता उजागर : जीतू पटवारी

मंगलवार को राऊ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आगामी 11 जनवरी को इंदौर में प्रस्तावित न्याय यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती उषा नायडू, इंदौर ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री विपिन वानखेड़े, सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे।

बैठक के उपरांत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार इंदौर में दूषित पानी पीने से पीड़ित परिजनों से मिलकर उनका दुख बाँटना चाहते थे, लेकिन मोहन यादव सरकार ने सैकड़ों पुलिस जवानों की तैनाती और बैरिकेडिंग कर उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोक दिया। यह घटना

स्पष्ट करती है कि प्रदेश सरकार सच्चाई और जवाबदेही से कितनी भयभीत है।

इसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी एवं प्रतिपक्ष के नेता श्री उमंग कांग्रेस ने आज इंदौर में जहरीला पानी पीने से मृतक पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर उनके दर्द और त्रासदी को वीडियो माध्यम से सार्वजनिक किया।

श्री पटवारी ने कहा अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में 17 लोगों की मौत दर्ज होने के बावजूद मात्र 4 पीड़ित परिवारों को ही दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। यह भाजपा सरकार की घोर असंवेदनशीलता, लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण है। जिन निर्दोष नागरिकों की जान गई, उनकी पीड़ा को यह सरकार आंकड़ों में दबाने का प्रयास कर रही है।

बैरिकेड के दौरान बहसबाजी भी हुई- इंदौर पुलिस ने बैरिकेड कर कांग्रेस नेताओं का रास्ता रोक दिया था। वहीं, नेता आगे बढ़ना चाहते थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी बहसबाजी भी हुई है। अपने लोगों को जीतू पटवारी ने वॉच टावर पर चढ़कर संबोधित भी किया है।

बाजार से 4000 करोड़ उठाएगी मोहन सरकार

तीन हिस्सों में लिया जाएगा कर्ज, नौ माह में 53100 करोड़ रुपए बाजार से उठाए

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल का पहला मंगलवार कर्ज के बोझ के साथ शुरू हो रहा है। सरकार मंगलवार को बाजार से 4 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की राशि बुधवार को मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश सरकार पहले ही 53100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मंगलवार को लिए जाने वाले नए कर्ज के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 57100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।